

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बावजूद 2025 में वैश्विक वृद्धि मजबूत बनी रही। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता का स्तर ऊंचा था, लेकिन दिसंबर में इसमें और कमी आई। वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों ने चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरण के बीच घरेलू कारकों से प्रेरित भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाया। दिसंबर के उच्च-आवृत्ति संकेतक मांग की अनुकूल परिस्थितियों के साथ वृद्धि की गति में निरंतरता का संकेत देते हैं। दिसंबर में शीर्ष सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन यह न्यूनतम सहनशीलता स्तर से नीचे रही। पिछले एक वर्ष में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ा है, जिसमें गैर-बैंक और बैंक दोनों स्रोतों ने ऋण वृद्धि में योगदान दिया है।

भूमिका

अनिश्चितताओं में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि आघात-सहनीय बनी रही। जनवरी 2026 में आईएमएफ द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अपडेट में प्रौद्योगिकी आधारित मजबूत निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन तथा व्यापक रूप से अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमानों को संशोधित किया गया। हालांकि, वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए जोखिम नकारात्मक पक्ष की ओर झुके रहे।

वैश्विक अनिश्चितता, हालांकि उच्च स्तर पर थी, दिसंबर में और कम हुई। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, माह के अधिकांश भाग में कम होने के बाद, बढ़ते भू-राजनीतिक दबावों के कारण जनवरी में थोड़ी बढ़ गई।

विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि धीमी होने के कारण दिसंबर में वैश्विक आर्थिक गतिविधि छह महीनों में सबसे निचले

* यह आलेख रेखा मिश्र, आशीष थॉमस जॉर्ज, शशि कांत, रजनी दहिया, बिस्वजीत मोहंती, ऊर्जा यादव, यामिनी झाम्ब, विकास आनंद, संजना सेजवाल, अर्जित शिवहरे, निलवा दास, आकाश राज, अमृता बसु, सत्येंद्र कुमार, लव कुमार शांडिल्य, राधिका सिंह, सुगंधी डी, हरि प्रसाद ई, शिव शंकर, श्वेता कुमारी, राकेश कुमार, अभिनंदन बोरड, अमित पवार, अपेक्षा शर्मा, समृद्धि, युवराज कश्यप, निशांत सिंह और सौरभ शर्मा द्वारा लिखा गया है। उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। बिनोद बिहारी बोई, राधेश्याम वर्मा और विद्या कमते द्वारा सहकर्मि समीक्षा के भी हम आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

स्तर पर पहुंच गई। विनिर्माण और सेवा निर्यात आदेशों में व्यापक गिरावट के कारण नए निर्यात आदेशों में फिर से संकुचन देखने को मिला।

दिसंबर में प्रमुख शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, गैर-अमेरिकी बाजारों ने बेहतर रिटर्न दिखाया क्योंकि निवेशकों ने अमेरिका में गहनता जोखिमों को लेकर चिंताओं के बीच अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई। जनवरी 2026 में अब तक, जापान के नेतृत्व में शेयर बाजारों में मध्य तक तेजी आई, लेकिन बाद में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं में वृद्धि के कारण गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक ब्याज दर अपेक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन, बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दर में वृद्धि और अमेरिका में बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई। उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह में उछाल आया, जिससे पिछले माह के बहिर्वाह में उलटफेर हुआ, जिसका नेतृत्व ऋण क्षेत्र में अंतर्वाह ने किया।

वैश्विक कमोडिटी कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले। औद्योगिक और कीमती धातुओं की कीमतों में मजबूती आई। दिसंबर में अनुकूल मांग-आपूर्ति संतुलन के चलते कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। जनवरी की शुरुआत में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कीमतों में मामूली उछाल आया, लेकिन बाद में आंशिक रूप से सुधार हुआ। मुद्रास्फीति में कमी आई, लेकिन लगातार सेवा क्षेत्र मुद्रास्फीति के कारण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में यह उच्च स्तर पर बनी रही। दिसंबर में मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों से प्रमुख केंद्रीय बैंकों के नीतिगत रुख में भिन्नता स्पष्ट हुई।

वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पहले अग्रिम अनुमानों से चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरण के बावजूद घरेलू कारकों – निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और स्थिर निवेश – द्वारा संचालित भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है। विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत सुधार और सेवा क्षेत्र में निरंतर उछाल से योजित सकल मूल्य (जीवीए) में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिसंबर के उच्च आवृत्ति संकेतक वृद्धि के लिए निरंतर सकारात्मक रुझान का संकेत देते हैं। ग्रामीण मांग में पुनरुत्थान और शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार के कारण मांग की स्थिति सकारात्मक बनी रही।

दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन लगातार चौथे महीने यह न्यूनतम सहनशीलता स्तर से नीचे बनी रही। दिसंबर में मुद्रास्फीति में यह उछाल खाद्य पदार्थों की अपस्फीति दर में कमी और कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में वृद्धि के कारण हुआ। कोर मुद्रास्फीति पर कीमती धातुओं की कीमतों का असमान रूप से प्रभाव बना रहा, जबकि स्वर्ण और चांदी को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर स्थिर रही। दिसंबर का आंकड़ा वर्तमान आधार वर्ष (2012=100) शृंखला में मुद्रास्फीति का अंतिम आंकड़ा है।

मुद्रा बाजार में, भारत औसत कॉल दर – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – नीतिगत रेपो दर से ऊपर रहा, लेकिन काफी हद तक निर्धारित सीमा के भीतर ही रहा। ट्रेजरी बिलों पर औसत प्रतिफल में गिरावट आई, जबकि वाणिज्यिक पत्रों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई। ऋण वृद्धि में तेजी के बाद आपूर्ति में अपेक्षित वृद्धि के कारण जमा प्रमाण पत्र पर ब्याज दरों में भी मामूली वृद्धि हुई। निर्धारित आय सेगमेंट में, जनवरी में सभी अवधियों के लिए प्रतिफल वक्र ऊपर की ओर स्थानांतरित हुआ। दिसंबर में बैंक जमा और ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक (31 दिसंबर तक), वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ा है, जिसमें बैंक स्रोतों के साथ-साथ गैर-बैंक स्रोतों ने भी ऋण वृद्धि में योगदान दिया है।

दिसंबर में भारतीय शेयर बाजारों में दोनों दिशाओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की मजबूत खरीदारी ने शेयर बाजारों को सहारा दिया, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा लगातार बिकवाली जारी रही। जनवरी 2026 में, अमेरिका द्वारा नई टैरिफ चेतावनियों के मद्देनजर शेयर बाजारों पर फिर से दबाव बढ़ने लगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में गतिरोध और रुपये के अवमूल्यन के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के बीच, दिसंबर में इक्विटी और ऋण दोनों क्षेत्रों से निवल विदेशी मुद्रा निवेश (एफपीआई) में बहिर्वाह दर्ज किया गया। सितंबर 2025 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय निवेश की बेहतर स्थिति से स्पष्ट है कि भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और

स्थिर चालू खाता घाटा भारत के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को सुदृढ़ बनाए हुए हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलावों को शामिल करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करता है। खंड IV भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. वैश्विक व्यवस्था

जनवरी 2026 में आईएमएफ के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अपडेट में वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया, हालांकि जोखिमों का संतुलन नकारात्मक पक्ष की ओर झुका रहा। अक्टूबर में जारी अनुमान की तुलना में वर्ष 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान को 10 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2026 के अनुमानों को 20 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया गया, जो मजबूत प्रौद्योगिकी-आधारित निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन तथा व्यापक रूप से अनुकूल वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है (सारणी II.1)। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र सहित प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि अनुमानों को भी ऊपर की ओर संशोधित किया गया। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, भारत और चीन के नेतृत्व में विकास मजबूत बना रहा। वर्ल्ड बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (जनवरी 2026) ने भी 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमानों को 40 बीपीएस बढ़ाकर 2.7 प्रतिशत कर दिया है, जो अमेरिका और यूरो क्षेत्र के नेतृत्व में प्रमुख आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षा से अधिक मजबूत वृद्धि को दर्शाता है (सारणी II.1)। वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमानों को भी 20 बीपीएस बढ़ाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, व्यापार वृद्धि में संभावित मंदी के कारण वश 2025 के स्तर से इसमें कमी आने की उम्मीद है।

दिसंबर में लगातार तीसरे महीने वैश्विक अनिश्चितता में गिरावट आई, हालांकि यह अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। वैश्विक नीति अनिश्चितता सूचकांक में धीमी गति से कमी आई, जबकि वैश्विक व्यापार अनिश्चितता सूचकांक में दिसंबर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। दिसंबर के अधिकांश समय

सारणी II.1: वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान – चुनिंदा एई और ईएमडीई
(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

संगठन अनुमान/पूर्वानुमान	आईएमएफ*					विश्व बैंक^					
	2025		2026		2027	2025		2026		2027	
पूर्वानुमान माह	अक्टू 2025	जन 2026*	अक्टू 2025	जन 2026	जन 2026	अक्टू 2025	जन 2026*	अक्टू 2025	जन 2026	अक्टू 2025	जन 2026
1. विश्व	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	2.3	2.7	2.4	2.6	2.6	2.7
2. उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	1.2	1.7	1.4	1.6	1.5	1.6
अमेरिका	2.0	2.1	2.1	2.4	2.0	1.4	2.1	1.6	2.2	1.9	1.9
यूके	1.3	1.4	1.3	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-
यूरो क्षेत्र	1.2	1.4	1.1	1.3	1.4	0.7	1.4	0.8	0.9	1.0	1.2
जापान	1.1	1.1	0.6	0.7	0.6	0.7	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8
3. उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.2	4.4	4.0	4.2	4.1	3.8	4.2	3.8	4.0	3.9	4.1
उभरता और विकासशील यूरोप	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	-	-	-	-	-	-
रूस	0.6	0.6	1.0	0.8	1.0	1.4	0.9	1.2	0.8	1.2	1.0
उभरता और विकासशील एशिया	5.2	5.4	4.7	5.0	4.8	-	-	-	-	-	-
भारत#	6.6	7.3	6.2	6.4	6.4	6.3	7.2	6.5	6.5	6.7	6.6
चीन	4.8	5.0	4.2	4.5	4.0	4.5	4.9	4.0	4.4	3.9	4.2
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	2.4	2.4	2.3	2.2	2.7	2.3	2.2	2.4	2.3	2.6	2.6
मेक्सिको	1.0	0.6	1.5	1.5	2.1	0.2	0.2	1.1	1.3	1.8	1.8
ब्राजील	2.4	2.5	1.9	1.6	2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	2.3	2.3
उप-सहारा अफ्रीका	4.1	4.4	4.4	4.6	4.6	3.7	4.0	4.1	4.3	4.3	4.5
दक्षिण अफ्रीका	1.1	1.3	1.2	1.4	1.5	0.7	1.3	1.1	1.4	1.5	1.5

टिप्पणी: 1. #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार (अप्रैल-मार्च) पर है।

2. &: अनुमान।

3. * वैश्विक वृद्धि दर को क्रय-शक्ति-समता भार पर मापा जाता है।

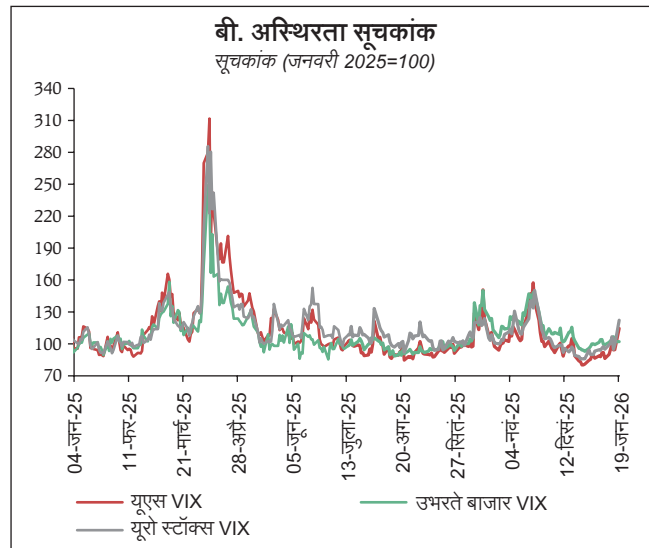
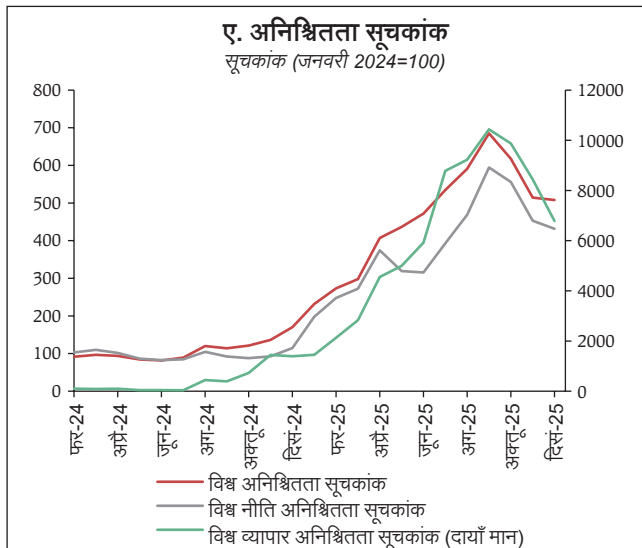
4. ^ वृद्धि दरों की गणना वर्ष 2010-19 की औसत कीमतों और बाजार विनियम दरों पर सकल घरेलू उत्पाद के भार का उपयोग करके की जाती है।

स्रोत: आईएमएफ, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, जनवरी 2026; और वर्ल्ड बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, जनवरी 2026।

में वित्तीय बाजार की अस्थिरता में मामूली कमी आई, जिसका मुख्य कारण प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता में कमी और जोखिम प्रीमियम में संकुचन था। भू-

राजनीतिक दबावों के फिर से बढ़ने के कारण जनवरी में वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में मामूली वृद्धि हुई (चार्ट II.1ए और II.1बी)।

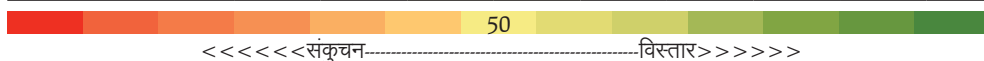
चार्ट II.1: वैश्विक अनिश्चितता और बाजार में उतार-चढ़ाव



स्रोत: शिकागो बोर्ड ऑफ़ ऑप्शंस एक्सचेंज; ब्लूमबर्ग: www.POLICYUNCERTAINTY.COM; और वैश्विक अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूआई) डेटाबेस।

सारणी II.2: दिसंबर में वैश्विक संयुक्त पीएमआई, निर्यात आदेश में कमी

	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
पीएमआई संयुक्त	52.6	51.8	51.5	52.1	50.8	51.2	51.7	52.5	52.9	52.5	53.0	52.7	52.0
पीएमआई विनिर्माण	49.6	50.1	50.6	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7	50.9	50.7	50.9	50.5	50.4
पीएमआई सेवाएँ	53.8	52.2	51.5	52.7	50.8	52	51.8	53.5	53.3	52.9	53.5	53.2	52.4
पीएमआई निर्यात आदेश	48.7	49.6	49.7	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5	48.9	49.7	48.6	50.0	49.2
पीएमआई निर्यात आदेश: विनिर्माण	48.2	49.4	49.6	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2	48.7	49.5	48.3	49.9	49.1
पीएमआई निर्यात आदेश: सेवाएँ	50.3	50.2	50.2	50.1	48.2	47.9	48.7	49.4	49.3	50.2	49.4	50.2	49.6



टिप्पणी: 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), एक डिफ्यूजन सूचकांक है, जो पिछले माह की तुलना में हर चर में हुए बदलाव को दिखाता है, यह बताता है कि हर चर बढ़ा/सुधरा है, गिरा/बिगड़ा है या बदला नहीं है। पीएमआई का मान 50 से ज्यादा होने पर बढ़ोतरी होती है; 50 से कम होने पर सिकुड़न होती है; और =50 होने पर 'कोई बदलाव नहीं' होता है।
 2. हीट मैप अप्रैल 2023 के बाद के डेटा पर लगाया जाता है। मैप कलर कोड होना है- लाल रंग सबसे कम मान दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं) दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई सीरीज में सबसे ज्यादा मान दिखाता है।

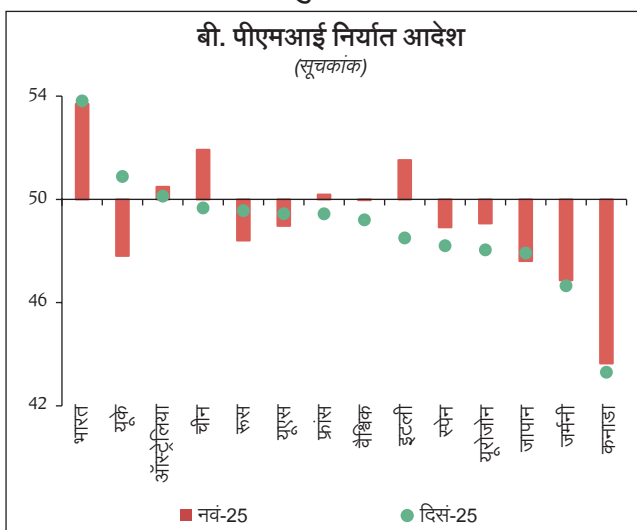
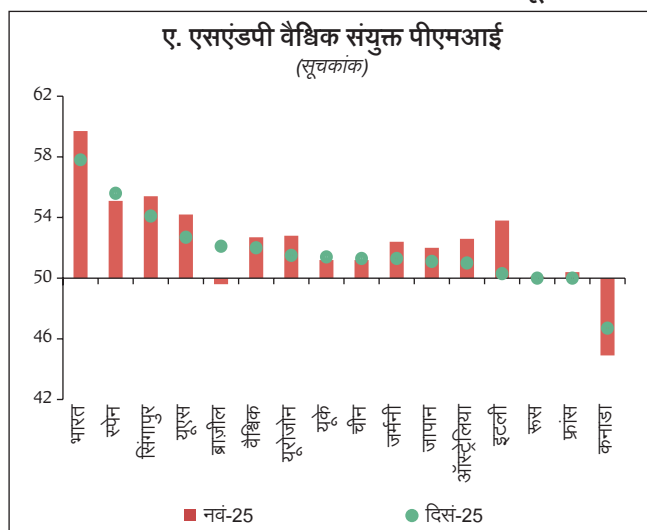
स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

विनिर्माण और सेवाओं में उत्पादन वृद्धि में कमी आने के कारण वैश्विक समग्र पीएमआई दिसंबर में घटकर छह महीनों के सबसे निचले स्तर पर आ गया। विनिर्माण और सेवाओं दोनों के निर्यात आदेशों में व्यापक गिरावट के कारण दिसंबर में नए निर्यात आदेशों में फिर से संकुचन देखने को मिला (सारणी II.2)।

पीएमआई सूचकांकों में परिलक्षित व्यावसायिक गतिविधि कनाडा को छोड़कर सभी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं

में विस्तारित हुई। प्रमुख ईएमडीई में, भारत और चीन में व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि हुई, जबकि रूस में यह लगभग अपरिवर्तित रही। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नए निर्यात आदेशों में गिरावट जारी रही। प्रमुख ईएमडीई में, भारत में निर्यात आदेशों में मजबूत गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि, चीन में बाह्य मांग में कमी के कारण नए निर्यात आदेशों में गिरावट आई (चार्ट II.2ए और II.2बी)।

चार्ट II.2: क्रय प्रबंधक सूचकांक: अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में तुलना



स्रोत: शिकागो बोर्ड ऑफ़ ऑप्शंस एक्सचेंज; ब्लूमबर्ग: www.POLICYUNCERTAINTY.COM; और वैश्विक अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूआई) डेटाबेस।

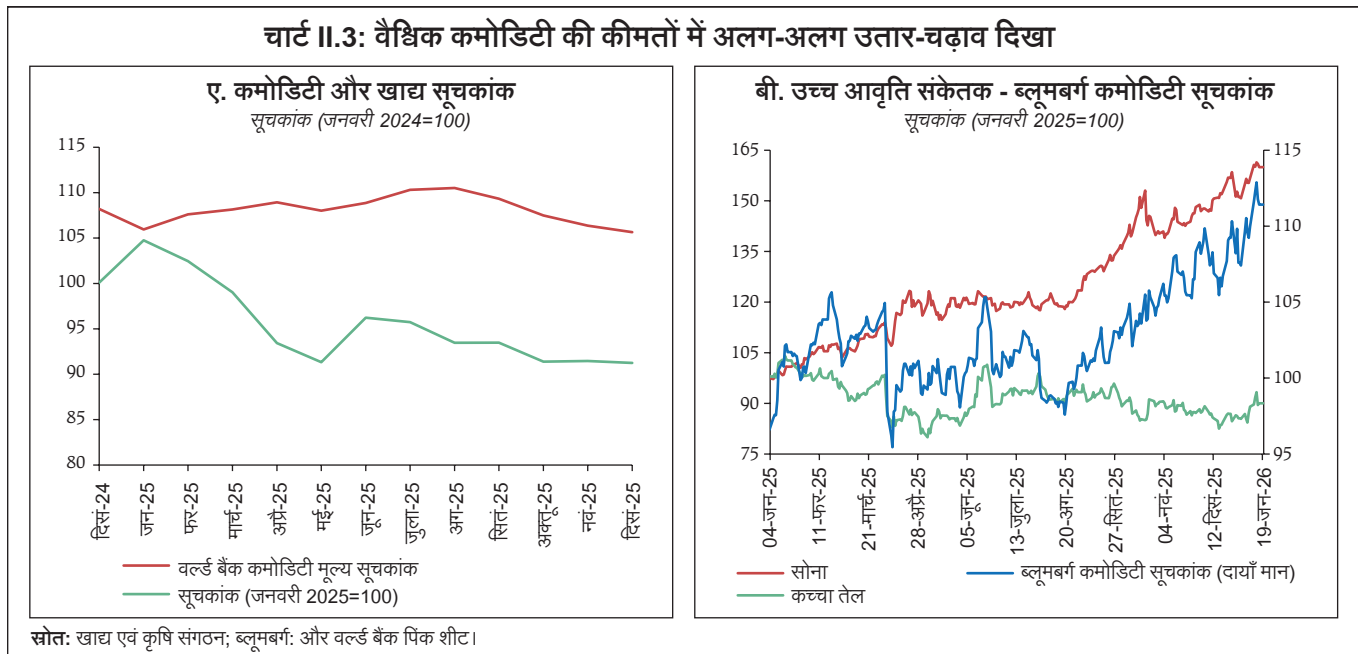
दिसंबर में वैश्विक कमोडिटी कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले। ऊर्जा की कीमतों में गिरावट के कारण वर्ल्ड बैंक कमोडिटी कीमत सूचकांक में मामूली गिरावट आई, जबकि धातुओं और कीमती धातुओं जैसी गैर-ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक लगातार चौथे माह गिरा, जिसका मुख्य कारण डेयरी उत्पाद, मांस और वनस्पति तेलों की कीमतों में गिरावट थी (चार्ट 11.3ए)। ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक में जनवरी में अब तक धातुओं और सोने की ऊंची कीमतों के कारण वृद्धि दर्ज की गई है। सोने की कीमतें, जो दिसंबर के अंत तक ऊपर की ओर बढ़ती रहीं, उसके बाद निवेशकों द्वारा वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन और मुनाफा वसूली के कारण गिर गईं। जनवरी में अब तक भू-राजनीतिक दबावों के फिर से बढ़ने के कारण कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें दिसंबर में सीमित दायरे में रहीं। भू-राजनीतिक दबावों में वृद्धि के बीच जनवरी की शुरुआत में कीमतों में तेजी आई, लेकिन बाद में आंशिक रूप से गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 11.3बी)।

आपूर्ति में कमी और टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के बीच हाल के समय में औद्योगिक धातुओं की कीमतों में काफी

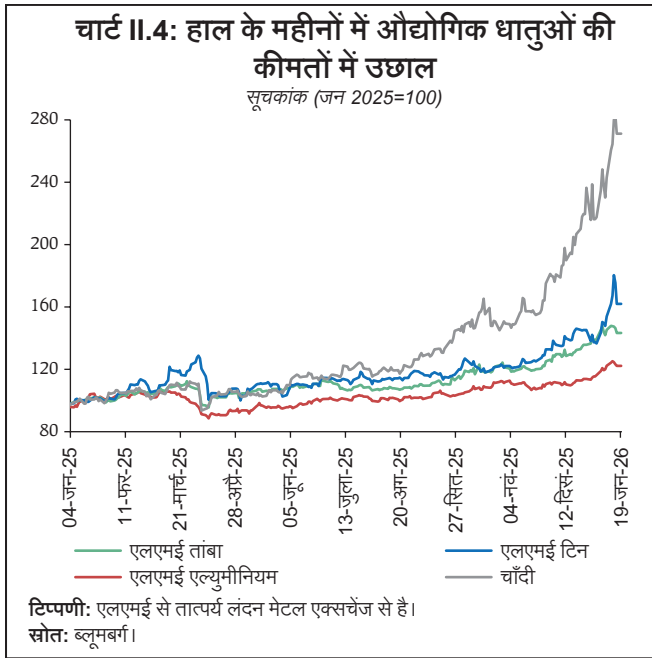
उछाल आया है। तांबे की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में मांग-आपूर्ति संतुलन बिगड़ने और अमेरिकी आयात टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं के कारण तेजी आई है। आपूर्ति में भारी कमी के कारण टिन की कीमतों में भी हाल के महीनों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। चीन की धातु गलाने की क्षमता पर लगी सीमा और यूरोप में उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में मजबूती आई है। चांदी की बढ़ती मांग के कारण, औद्योगिक उपयोग और सुरक्षित निवेश के रूप में, आपूर्ति में कमी के बीच इसकी कीमतों में भी उछाल आया है (चार्ट 11.4)।

मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई, लेकिन सेवाओं में लगातार मुद्रास्फीति के कारण अधिकांश विकासशील देशों में यह उच्च स्तर पर बनी रही। यूरो क्षेत्र में, ऊर्जा लागत में गिरावट के कारण दिसंबर में मुख्य मुद्रास्फीति में और कमी आई, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति स्थिर रही। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण ब्रिटेन में मुद्रास्फीति छह महीने के निचले स्तर पर आ गई। जापान में भी खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 11.5ए)। प्रमुख विकासशील देशों में, चीन में खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, जबकि मूल मुद्रास्फीति स्थिर रही। इसके विपरीत,

चार्ट 11.3: वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव दिखा



¹ 1 खाद्य एवं कृषि संगठन के दिसंबर 2025 माह के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार।

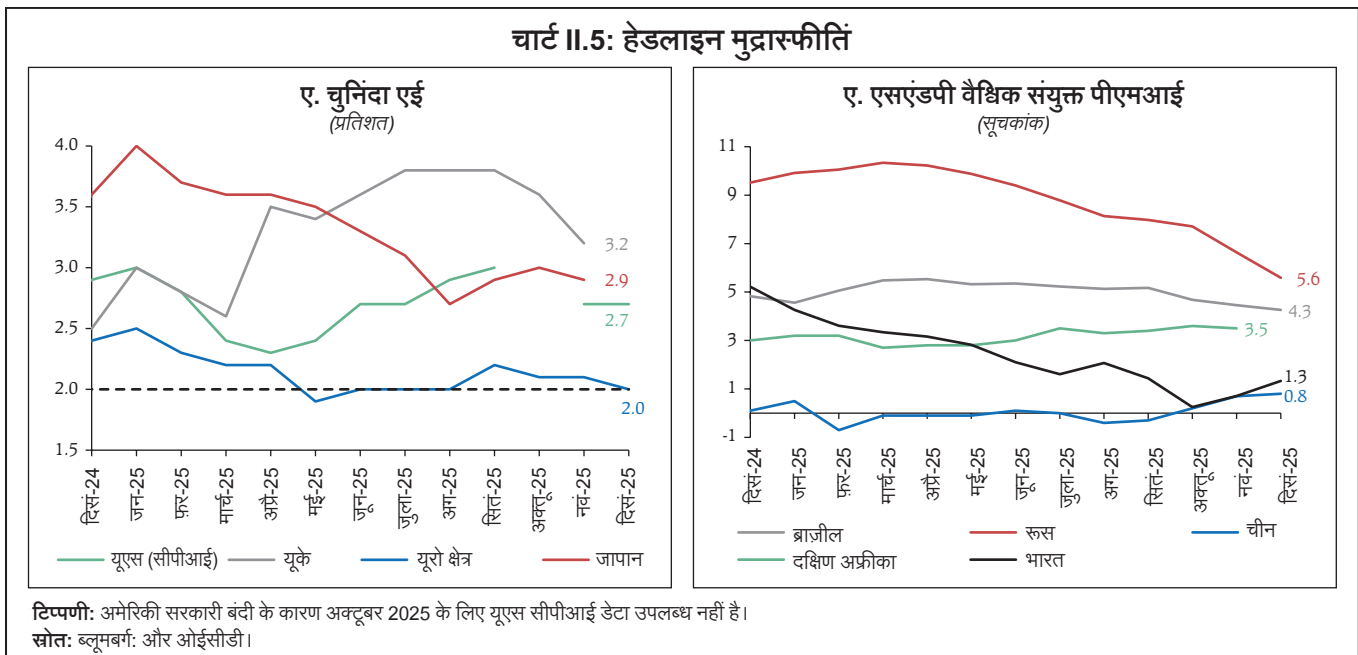


ब्राजील और रूस में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ, जहां मुख्य मुद्रास्फीति सितंबर 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। परिवहन लागत में कमी के कारण दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति में कमी आई (चार्ट II.5बी)।

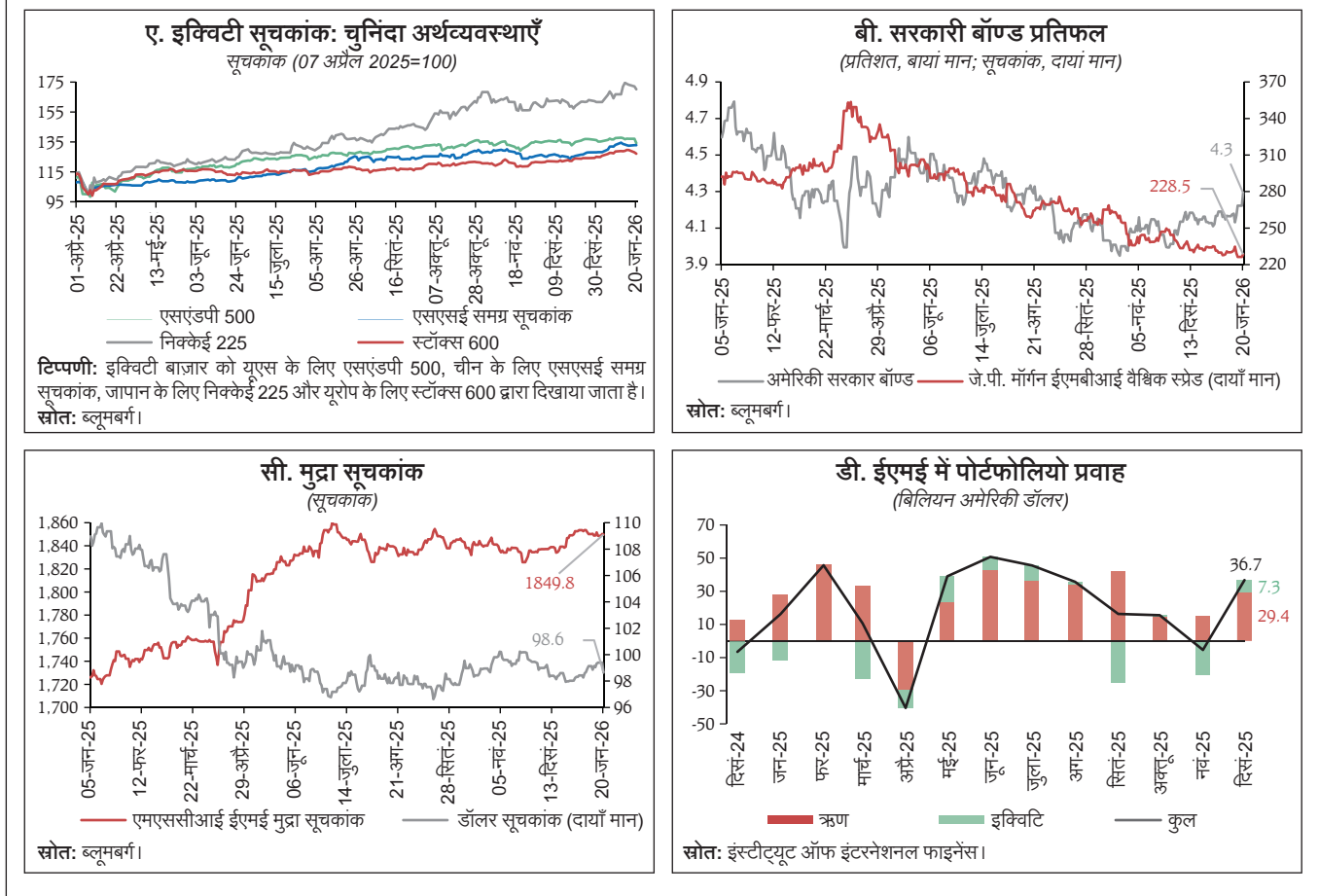
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों में दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में तेजी देखी गई, लेकिन बाद में बढ़ती

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण इनमें गिरावट आई। अमेरिकी शेयर बाजारों में दिसंबर और जनवरी में असामान्य रूप से अस्थिरता बनी रही। दिसंबर के मध्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिकवाली के कारण बाजारों में गिरावट आई, लेकिन अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद इनमें सुधार हुआ। इसके बाद, भू-राजनीतिक दबावों के कारण गिरावट दर्ज करने से पहले, बाजार जनवरी के मध्य तक सीमित दायरे में रहे। यूरोपीय शेयर बाजार दिसंबर में मोटे तौर पर स्थिर रहे, लेकिन बढ़ते भू-राजनीतिक दबावों के कारण जनवरी के मध्य से इनमें गिरावट आई। जापान के शेयर बाजारों में, हालांकि बीच-बीच में गिरावट देखी गई, दिसंबर में मामूली बढ़त दर्ज की गई। भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण गिरावट से पहले, बाजारों ने जनवरी के मध्य तक बढ़त दर्ज की। सकारात्मक घरेलू आंकड़ों के कारण चीनी शेयर बाजार दिसंबर के मध्य से मजबूत हुए। हालांकि, व्यापार पर विनियामकीय जांच बढ़ने के कारण जनवरी के मध्य के आसपास इनमें नरमी आई (चार्ट II.6ए)।

दिसंबर की शुरुआत में, बैंक ऑफ जापान के सख्त रुख के बाद अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड पर ब्याज दरें बढ़ गईं, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी मुद्रास्फीति में कमी के बाद इनमें कुछ नरमी आई। हालांकि, मजबूत आर्थिक



चार्ट II.6 : वैश्विक वित्तीय बाजार

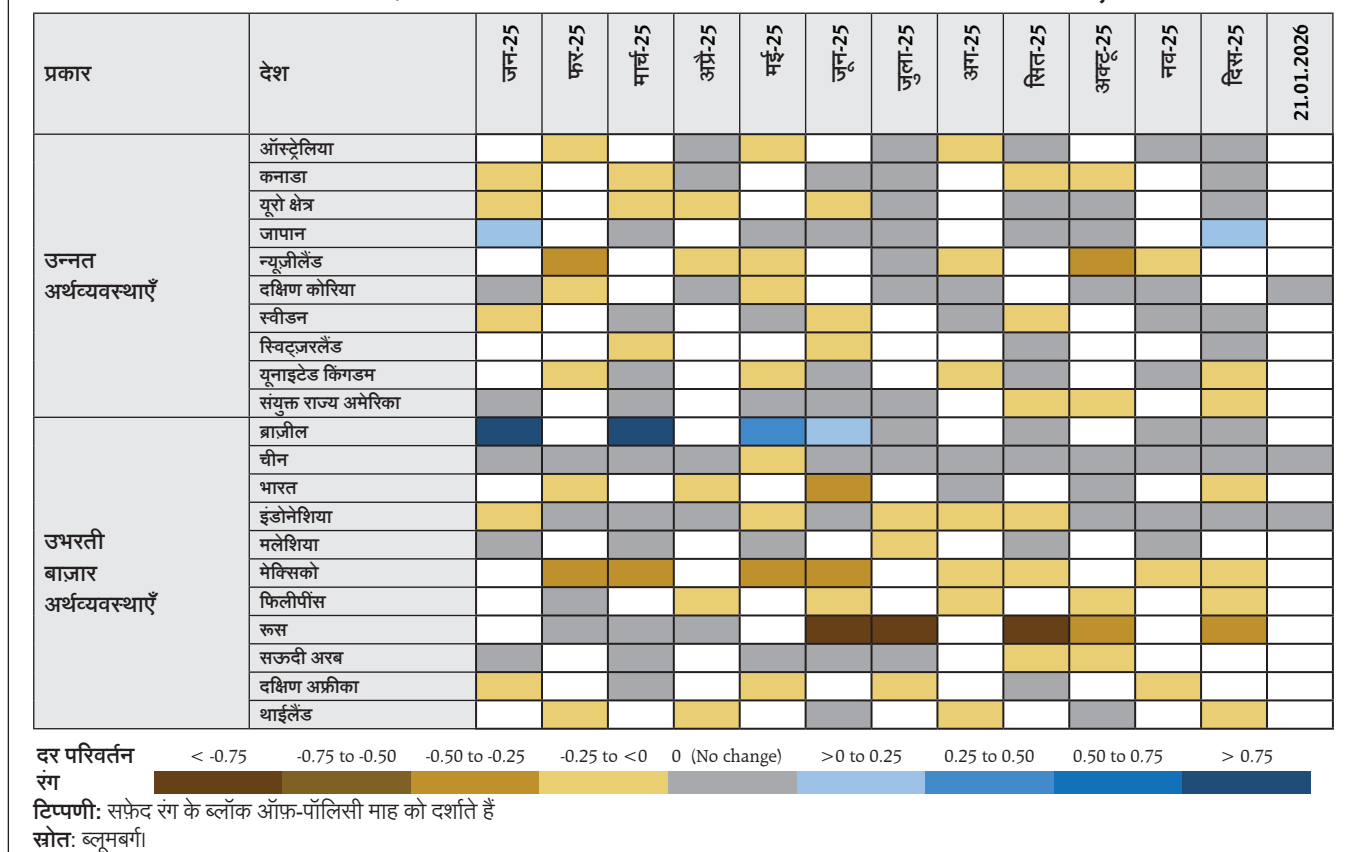


आंकड़ों और एफओएमसी की बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के बाद, जिसमें भविष्य में मौद्रिक नीति में ढील की धीमी गति का संकेत मिला, ब्याज दरें वर्ष के अंत तक फिर से बढ़ गईं। जनवरी में अब तक, कमजोर श्रम आंकड़ों के कारण ब्याज दरें कम हुईं, लेकिन जापानी सरकारी ऋण में भारी बिकवाली के कारण वैश्विक बॉण्ड की बिकवाली से इनमें फिर से वृद्धि हुई। सकारात्मक निवेशक मांग के समर्थन से दिसंबर और जनवरी में जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार बॉण्ड ब्याज दर में अंतर कम हुआ (चार्ट II.6बी)। फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद दिसंबर के अधिकांश समय में अमेरिकी डॉलर का मूल्यहास हुआ, लेकिन तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों के चलते इसमें सुधार हुआ (चार्ट II.6सी)। कमजोर अमेरिकी डॉलर, एशिया के लिए बेहतर दृष्टिकोण और निवेशकों द्वारा अमेरिकी आस्तियों से हटकर

अन्य निवेश विकल्पों में विविधता लाने के कारण उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट II.6डी)।

दिसंबर 2025 में, प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों में भिन्नता देखने को मिली। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका और ब्रिटेन ने कमजोर श्रम बाजार स्थितियों के जवाब में नीतिगत दरों में कमी की, जबकि जापान ने मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रहने के कारण अपनी नीतिगत दर को तीन दशक के उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। ईएमडीई के मामले में, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि रूस, फिलीपींस, थाईलैंड और मैक्सिको ने दरों में कटौती की। जनवरी में अब तक, चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया ने अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है (चार्ट II.7)।

चार्ट II.7: केंद्रीय बैंकों ने दिसंबर में अलग-अलग नीतिगत दरों के रास्ते अपनाए



III. घरेलू गतिविधियां

वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं, जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वास्तविक जीडीपी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। मांग पक्ष में, पीएफसीई और स्थिर निवेश प्रमुख वृद्धि कारक रहे। आपूर्ति पक्ष में, विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत सुधार और सेवा क्षेत्र में निरंतर उछाल ने सकल लाभ वृद्धि को बढ़ावा दिया। दिसंबर के उच्च आवृत्ति संकेतक वृद्धि के लिए निरंतर उछाल का संकेत देते हैं। ग्रामीण मांग में पुनरुत्थान और शहरी मांग में धीरे-धीरे हो रही रिकवरी के कारण मांग की स्थिति सकारात्मक बनी रही।

सकल मांग

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय आघात-सहनशीलता दिखाई, और वर्ष 2025-26 में

वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो एक वर्ष पहले 6.5 प्रतिशत थी²

वर्ष 2025-26 में, कुल मांग के मुख्य आधार, पीएफसीई में वृद्धि लगभग स्थिर रही, जबकि स्थिर निवेश में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुई। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में भी तेजी आई, जिससे समग्र वृद्धि की गति को और बल मिला। पीएफसीई की वृद्धि ग्रामीण मांग में निरंतरता और शहरी मांग में क्रमिक सुधार से समर्थित थी, जिसका कुछ श्रेय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण को दिया जा सकता है।³

बाह्य मोर्चे पर, निवल निर्यात ने वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला। भारत के कुल निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिसे

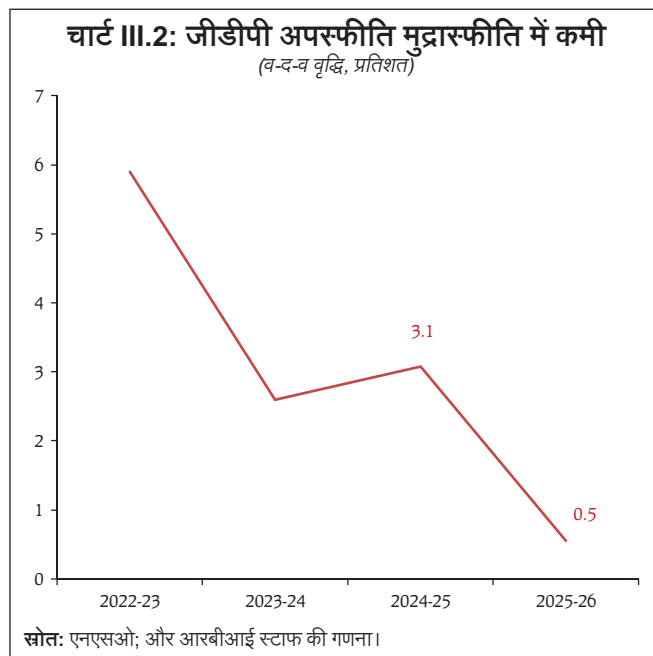
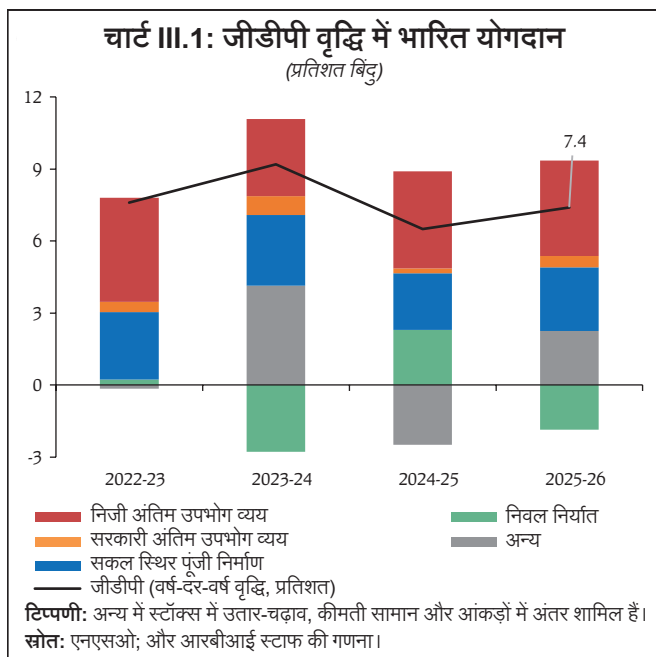
² वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

³ 3 जीएसटी युक्तिकरण की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई थी और इसे 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया था।

सेवाओं के स्थिर प्रदर्शन का समर्थन मिला, हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के बाद माल निर्यात कमजोर हो गया।⁴ दूसरी ओर, आयात में वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक रही, जिसका आंशिक कारण आधार प्रभाव था (चार्ट III.1 और अनुबंध सारणी ए1)।

वर्ष 2025-26 में मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बावजूद, नाममात्र जीडीपी वृद्धि पाँच वर्षों में सबसे कम 8.0 प्रतिशत पर पहुँच गई। नाममात्र और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच अंतर में कमी जीडीपी अपस्फीति मुद्रास्फीति में गिरावट में परिलक्षित हुई, जो वर्ष 2025-26 में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई (चार्ट III.2)।

दिसंबर में आर्थिक गतिविधियों में मजबूत वृद्धि जारी रही। जीएसटी दरों के युक्तिकरण, स्टॉक निकासी और कंपनियों द्वारा वर्ष के अंत के बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों के कारण ई-वे बिल जनरेशन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी



राजस्व संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से आयात से संबंधित जीएसटी प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।⁵ माह के दौरान यात्रा और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम खपत में तेजी आई।⁶ सर्दियों से संबंधित मांग में तेजी आने के साथ बिजली की मांग में सुधार हुआ। डिजिटल भुगतान मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में मजबूत वृद्धि बनाए रखने में सफल रहा (सारणी III.1)।

दिसंबर में समग्र मांग की स्थिति सकारात्मक बनी रही। ग्रामीण मांग के संकेतकों में तेजी आई और सभी श्रेणियों में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। जीएसटी दरों में कटौती के बाद बढ़ी हुई सामर्थ्य, वर्ष के अंत के प्रचार प्रस्तावों और जनवरी में अपेक्षित मूल्य संशोधन से पहले बढ़ी मांग के कारण ऑटोमोबाइल बिक्री में वृद्धि हुई। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और जीएसटी के युक्तिकरण के कारण दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की खुदरा

⁴ अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इसमें 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी 25 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ और 27 अगस्त 2025 से प्रभावी अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को जोड़ा गया।

⁵ आयात से संबंधित जीएसटी प्राप्तियों में दिसंबर में 19.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

⁶ दिसंबर में भारत की पेट्रोलियम खपत बढ़कर 21.75 मिलियन मीट्रिक टन हो गई, जो रिकॉर्ड पर उच्चतम मासिक स्तर है।

सारणी III.1: समग्र आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक

संकेतक	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
जीएसटी ई-वे बिल	17.6	23.1	14.7	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8	22.4	21.0	8.2	27.6	23.5
जीएसटी राजस्व	-0.2	12.3	9.1	9.9	12.6	16.4	6.2	7.5	6.5	9.1	4.6	3.6	6.1
टोल संग्रह	9.8	14.8	18.7	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8	16.1	13.8	4.6	2.9	0.4
विद्युत की मांग	5.1	1.3	2.4	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.6	3.8	3.5	-5.8	-0.6	6.5
पेट्रोलियम खपत	2.0	3.0	-5.2	-3.1	0.2	1.1	0.5	-4.4	4.8	7.0	-1.5	2.8	5.3
जिसमें													
पेट्रोल	11.1	6.7	5.0	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9	5.5	8.0	7.4	2.6	7.1
डीजल	5.9	4.2	-1.3	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4	1.2	6.5	-0.3	4.7	5.0
विमानन टरबाइन ईंधन	8.7	9.4	4.2	5.7	3.9	4.4	3.3	-2.3	-2.9	-0.8	2.1	5.4	0.3
डिजिटल भुगतान – मात्रा	33.1	33.0	26.7	30.8	30.0	29.2	28.3	30.9	31.1	28.1	21.5	30.2	23.7
डिजिटल भुगतान – मूल्य	19.6	18.6	9.5	17.3	18.4	12.6	17.4	16.6	5.3	13.4	8.8	14.7	15.4

< <संकुचन ----- विस्तार>>

- टिप्पणी:** 1. सभी संकेतकों की व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
 2. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। दिसंबर 2025 के लिए डिजिटल भुगतान डेटा अनंतिम है।
 3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग उस डेटा सीरीज की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।
 4. दिसंबर 2025 के लिए टोल संग्रह की वृद्धि दर के डेटा की गणना प्रतिदिन के डेटा को मिलाकर की जाती है।

स्रोत: माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); आरबीआई: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए); नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई); और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, भारत सरकार।

बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा यात्री वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसने पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। हालांकि, घरेलू हवाई यात्री यातायात में गिरावट दर्ज की गई, जिसका आंशिक कारण दिसंबर की शुरुआत में घने शीतकालीन कोहरे और उड़ान समयक्रम में व्यवधान था (सारणी III.2)।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (16 जनवरी 2026 को जारी) के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर में दिसंबर में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण दर स्थिर रही और शहरी दर में थोड़ी वृद्धि हुई। श्रम बल सहभागिता दर जून से चली आ रही अपनी बढ़ती प्रवृत्ति को जारी रखती है। विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई रोजगार दिसंबर में थोड़ा कम हुआ लेकिन विस्तार

सारणी III.2: उच्च आवृत्ति संकेतक - उच्च मांग स्थिति

	संकेतक	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
शहरी मांग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	10.8	14.1	12.1	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.5	-0.5	-2.5	3.5	7.0	-3.6
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	0.1	15.5	-10.3	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8	0.9	5.8	10.7	19.7	26.6
ग्रामीण मांग	खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री	-12.5	6.6	-7.2	-0.7	2.9	5.4	4.8	-4.3	2.8	5.2	40.5	2.1	14.6
	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री	25.8	5.2	-14.5	-5.7	7.6	2.8	8.7	11.0	30.1	3.6	14.2	56.5	15.8
	खुदरा दोपहिया वाहनों की बिक्री	-17.6	4.2	-6.3	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5	2.2	6.5	51.8	-3.1	9.5

< <संकुचन ----- विस्तार>>

- टिप्पणी:** 1. सभी संकेतकों की व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
 2. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है।
 3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग उस डेटा सीरीज की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।
 4. दिसंबर 2025 के लिए टोल संग्रह की वृद्धि दर के डेटा की गणना प्रतिदिन के डेटा को मिलाकर की जाती है।
 5. खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री के डेटा में दो पहिया, तीन पहिया, यात्री वाहन, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री शामिल है।

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; ऑटोमोबाइल डीलर्स संघों का महासंघ (फाडा); और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

क्षेत्र में बना रहा, जबकि सेवाओं में पीएमआई रोजगार में साढ़े तीन वर्षों में पहली बार संकुचन देखा गया।⁷ दिसंबर में नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण बीमा, आतिथ्य और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों में नई भर्तियां थीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग दिसंबर में लगातार छठे महीने संकुचन में रही, जो ग्रामीण श्रम बाजार की स्थितियों में निरंतर सुधार को दर्शाता है (सारणी III.3)।

दिसंबर में, सरकार ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम पेश किया, जिसने मनरेगा अधिनियम, 2005 का स्थान लिया। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों

के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार की बढ़ी हुई सांविधिक गारंटी प्रदान करता है, साथ ही परिणाम-आधारित ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को मजबूत करता है।

अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान, बजट अनुमानों (बीई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक थे (चार्ट III.3ए)⁸ उच्च राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों में मंदी के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि के कारण था।⁹ प्रत्यक्ष कर संग्रह में मंदी और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में मामूली संकुचन के कारण सकल कर राजस्व वृद्धि धीमी हो गई।¹⁰

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के अनुपात में, अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान राज्यों के घाटे के संकेतक पिछले वर्ष की

सारणी III.3: रोजगार के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक

सूचकांक	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: अखिल भारतीय)					5.1	5.6	5.6	5.2	5.1	5.2	5.2	4.7	4.8
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: ग्रामीण)					4.5	5.1	4.9	4.4	4.3	4.6	4.4	3.9	3.9
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: शहरी)					6.5	6.9	7.1	7.2	6.7	6.8	7.0	6.5	6.7
नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक	8.7	3.9	4.0	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8	3.4	10.1	-9.3	23.5	13.2
पीएमआई रोजगार: विनिर्माण	53.4	54.8	54.5	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3	53.1	52.1	52.4	50.9	50.5
पीएमआई रोजगार: सेवाएँ	55.5	56.3	56.2	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4	52.2	51.9	51.4	51.6	49.8
मनरेगा: काम की मांग	8.2	14.4	2.8	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3	-26.2	-27.1	-35.1	-32.0	-28.9

<<संकुचन ----- विस्तार>>

टिप्पणी: 1. सभी पीएलएफएस संकेतक मौजूदा चालू सप्ताह के हैं और 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हैं।
 2. नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक और मनरेगा में काम की मांग के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
 3. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है।
 4. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग उस डेटा सीरीज की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।
 5. सभी पीएमआई वैल्यू सूचकांक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई वैल्यू >50 का मतलब है विस्तार, <50 का मतलब है संकुचन और =50 का मतलब है 'कोई बदलाव नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वैल्यू) दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; इन्फो एज; और एस एंड पी ग्लोबल।

⁷ पीएमआई रोजगार में, लगभग 2 प्रतिशत फर्मों ने नौकरी में कटौती की सूचना दी, जबकि अधिकतम ने कोई बदलाव नहीं होने का संकेत दिया।

⁸ महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

⁹ अप्रैल-नवंबर 2025-26 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत थी। निवल कर राजस्व में 3.4 प्रतिशत की गिरावट के कारण केंद्र की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में कमी आई।

¹⁰ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वृद्धि अप्रैल-नवंबर 2024-25 में 13.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-नवंबर 2025-26 में क्रमशः 7.0 प्रतिशत और (-) 1.1 प्रतिशत हो गई। प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर श्रेणियों में, निगम कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की।

समान अवधि की तुलना में कम रहे (चार्ट III.3बी)। यह सुधार बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व व्यय में कमी के कारण हुआ। इसके विपरीत, पूंजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की गिरावट से उबरकर सकारात्मक रही, जिससे व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राजस्व प्राप्तियों में, राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से वृद्धि हुई, जबकि केंद्र से प्राप्त अनुदान में कमी आई।

व्यापार

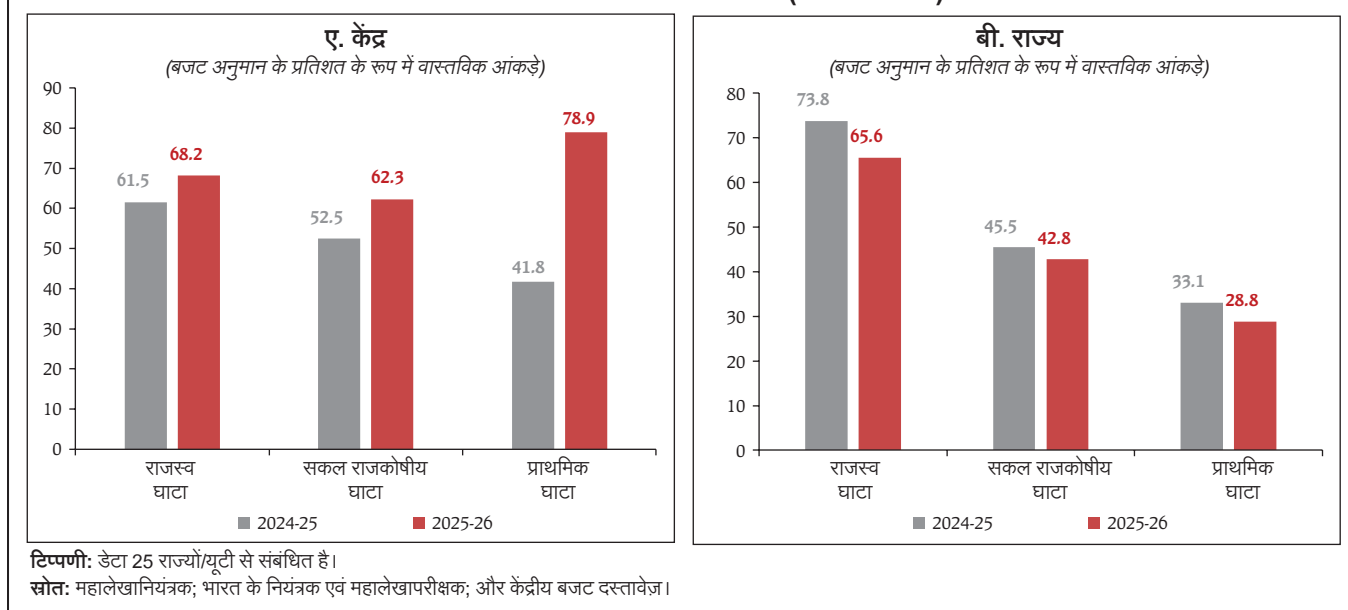
इस वर्ष अब तक (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्वर्ण के कारण, पण्य वस्तु व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था।¹¹

इस अवधि के दौरान भारत के पण्य वस्तु निर्यात और आयात में व्यापक विस्तार देखा गया।¹²

दिसंबर में, निर्यात की तुलना में आयात की अधिक वृद्धि के कारण पण्य वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया (चार्ट III.4)।¹³ दिसंबर में स्वर्ण के आयात में गिरावट आई, जबकि चांदी के आयात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर में समुद्री उत्पादों और लौह अयस्क के निर्यात से समर्थित, चीन को निर्यात दो अंकों में बना रहा।¹⁴

अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात और आयात दोनों में ईरान की

चार्ट III.3 सरकारी घाटा संकेतक (अप्रैल-नवंबर)



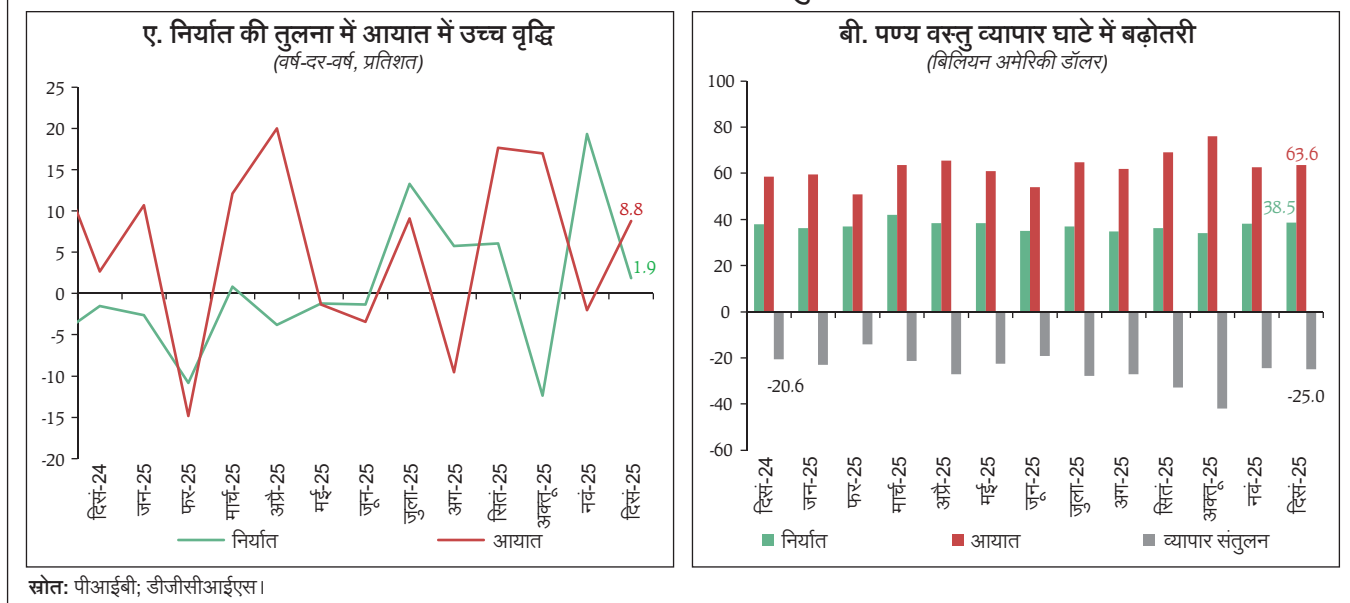
¹¹ अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान पण्य वस्तु व्यापार घाटा 248.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान यह 223.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

¹² वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 18 (निर्यात बास्केट का 56.4 प्रतिशत) और 30 प्रमुख वस्तुओं में से 18 (आयात बास्केट का 35.4 प्रतिशत हिस्सा) ने विस्तार दर्ज किया।

¹³ पण्य वस्तु व्यापार घाटा दिसंबर 2025 में बढ़कर 25.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो दिसंबर 2024 में 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर 2025 में व्यापारिक निर्यात 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था [1.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि]। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मांस, डेयरी और पोल्ट्री जैसे प्रमुख खंड; ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स; इंजीनियरिंग सामान; और समुद्री उत्पादों ने निर्यात को बढ़ाया, जबकि चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक और लिनोलियम, तेल भोजन और रत्न और आभूषण ने निर्यात को कम किया। शीर्ष 20 प्रमुख गंतव्यों में से 8 में निर्यात का विस्तार हुआ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी जैसे गंतव्यों के निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका, नीदरलैंड और यूके में कमी आई। दिसंबर 2025 में व्यापारिक आयात 63.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था [8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) का विस्तार]। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम क्लूड और उत्पाद, अलौह धातु, धातु अयस्क और अन्य खनिजों ने आयात में धनात्मक योगदान दिया, जबकि स्वर्ण, परिवहन उपकरण, लोहा और इस्पात, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, और लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों ने महीने के दौरान आयात में गिरावट दर्ज की। 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 से आयात का विस्तार हुआ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे गंतव्यों से आयात बढ़ रहा है, जबकि रूस, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया में कमी आई।

¹⁴ दिसंबर 2025 में चीन को निर्यात में 67.4 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई।

चार्ट III.4: भारत का पण्य वस्तु व्यापार



हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से भी कम है।¹⁵ अगस्त के अंत में अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद, नवंबर 2025 को छोड़कर, बाद के महीनों में भारत का अमेरिका को निर्यात घट गया।

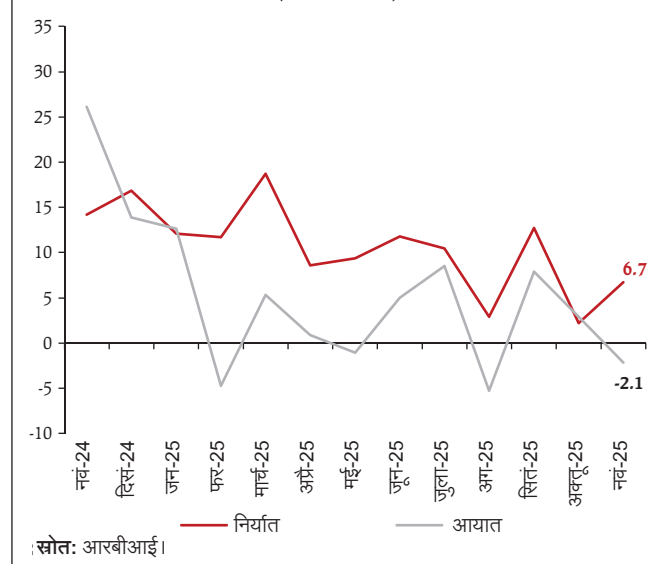
नवंबर में निवल सेवा निर्यात में वृद्धि हुई, निर्यात में तेजी आई और आयात में गिरावट आई (चार्ट III.5)।¹⁶ नवंबर में सेवा निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से व्यवसाय, कंप्यूटर और परिवहन सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण हुई। मुख्य रूप से व्यवसाय और परिवहन सेवाओं के आयात में गिरावट के कारण सेवा आयात में संकुचन हुआ।

कुल आपूर्ति

आपूर्ति पक्ष की देखें तो, मूल कीमतों पर वास्तविक जीवीए में वृद्धि वर्ष 2024-25 के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में कुछ मंदी के

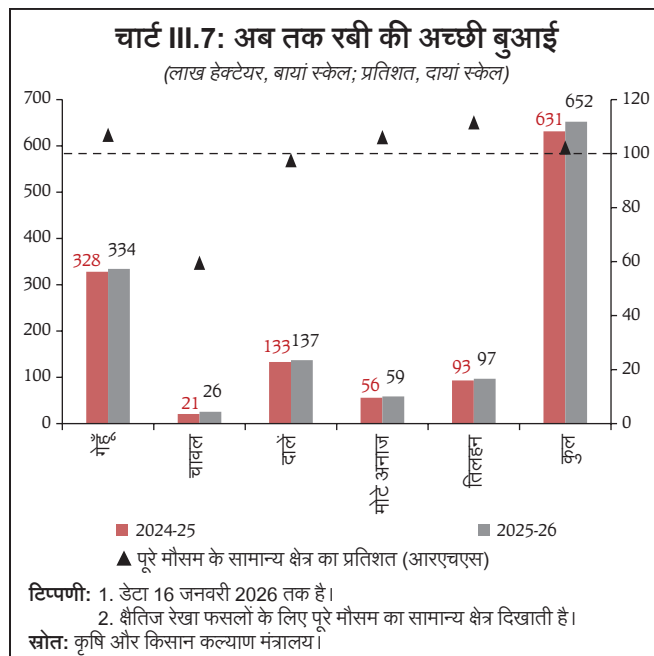
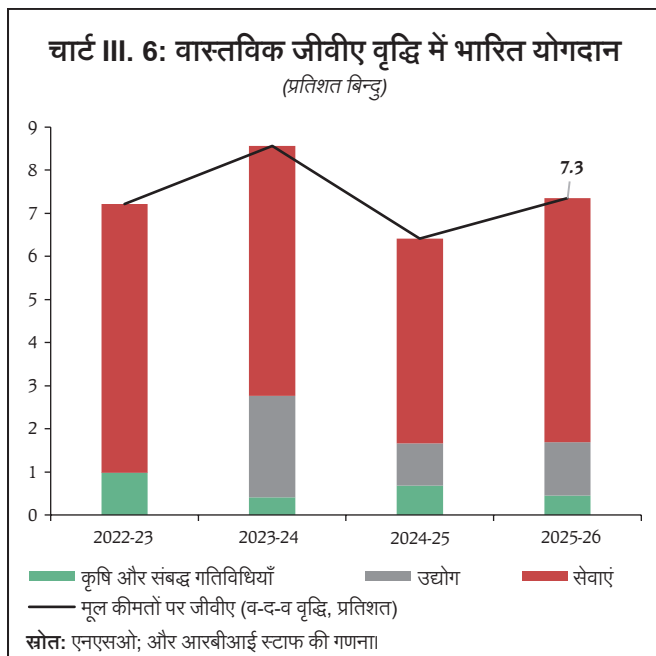
बावजूद, सेवा क्षेत्र में मजबूती और औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर गतिविधि के कारण यह तेजी आई है (चार्ट III.6 और अनुबंध सारणी ए2)। विनिर्माण क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के कारण औद्योगिक क्षेत्र में तेजी आई। सेवा क्षेत्र में गति बनी रही, जिसमें वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने समग्र वृद्धि को गति प्रदान की। कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि में मंदी देखी गई।

चार्ट III.5: सेवा निर्यात बढ़ा जबकि आयात घटा
(व-द-व, प्रतिशत)



¹⁵ वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी 0.3 प्रतिशत और भारत के कुल आयात में 0.06 प्रतिशत थी। ईरान को प्रमुख निर्यात वस्तु चावल है, जबकि प्रमुख आयात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं।

¹⁶ निवल सेवा निर्यात नवंबर 2025 में 17.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो नवंबर 2024 में 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान, निवल सेवा निर्यात अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान 116.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 133.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।



कृषि

रबी की बुवाई का मौसम लगभग पूरा हो चुका है, और अब तक सभी प्रमुख फसलों में अधिक रकबा दर्ज किया गया है।¹⁷ मानसून के बाद के मौसम में अनुकूल वर्षा के कारण रबी की बुवाई में अच्छी प्रगति हुई।¹⁸ शीर्ष पांच रबी उत्पादक राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान - में कम तापमान और पर्याप्त मिट्टी की नमी के संयोजन ने फसल वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है (चार्ट III.7)।¹⁹

खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए अब तक चावल की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।²⁰ परिणामस्वरूप, सरकार के पास चावल और गेहूं का संयुक्त सार्वजनिक भंडार

¹⁷ 16 जनवरी 2026 तक, रबी फसलों के तहत बोए गए क्षेत्र ने पूरे सीजन के सामान्य रकबे के 102.3 प्रतिशत को कवर किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है।

¹⁸ सामान्य से अधिक मॉनसून के बाद वर्षा के कारण, जलाशयों का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि और दशकीय औसत की तुलना में अधिक बना हुआ है। 15 जनवरी 2026 तक, देश भर के 166 प्रमुख जलाशयों में औसत भंडारण पूर्ण क्षमता का 74 प्रतिशत था - एक वर्ष पहले की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक और दशकीय औसत से 23.9 प्रतिशत अधिक।

¹⁹ दिसंबर 2025 तक रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर।

²⁰ 19 जनवरी 2026 तक चावल की खरीद 410.1 लाख टन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.1 प्रतिशत अधिक है।

भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है।²¹

औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक

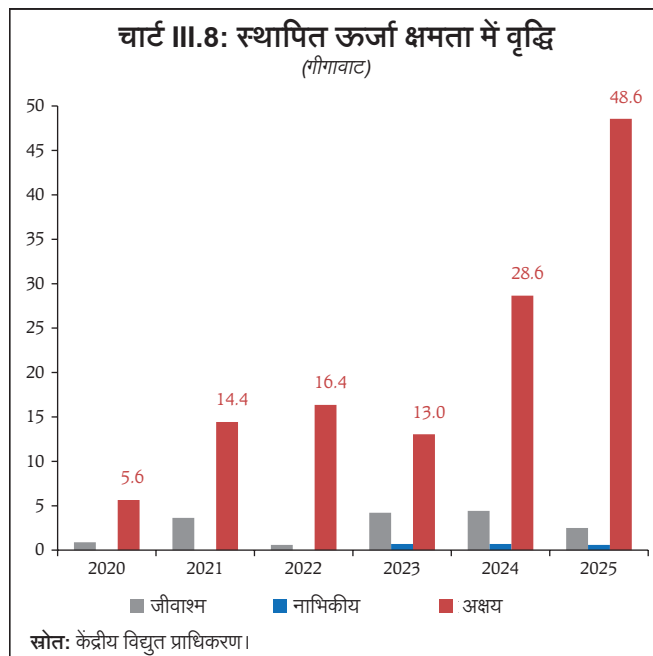
नवंबर में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वार्षिक आधार पर हुई वृद्धि के अनुसार, औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि 25 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि थी। खनन क्षेत्र में भी लगातार दो महीनों की गिरावट के बाद सुधार देखने को मिला। इस्पात और सीमेंट में मजबूत वृद्धि और बिजली उत्पादन में आए बदलाव के कारण दिसंबर में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में चार माह का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया।

दिसंबर में औद्योगिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतक मजबूत बने रहे। दिसंबर में ऑटोमोबाइल उत्पादन में सभी क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण आयकर राहत, जीएसटी युक्तिकरण और आसान वित्तपोषण शर्तों सहित

²¹ 01 जनवरी, 2026 तक चावल और गेहूं का स्टॉक क्रमशः 679.3 लाख टन (बफर मानदंड का 8.9 गुना) और 274.6 लाख टन (बफर मानदंड का 2.0 गुना) था।

नीतिगत समर्थन से प्रेरित मजबूत बुकिंग पाइपलाइन थी। खरीफ की अच्छी पैदावार से प्राप्त बेहतर नकदी प्रवाह के कारण ट्रैक्टर उत्पादन में भी उछाल आया। लगातार दो महीनों से घट रही बिजली उत्पादन में दिसंबर में सुधार हुआ। नए ऑर्डर और उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण कुछ मंदा के बावजूद विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि जारी रही (सारणी III.4)।

भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के कारण पिछले पांच वर्षों में स्थापित विद्युत क्षमता में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में हुई वृद्धि थी (चार्ट III.8)।



सारणी III.4: उच्च आवृत्ति संकेतक-उद्योग-वृद्धि दर

संकेतक	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
आईआईपी-हेडलाइन	3.7	5.2	2.7	3.9	2.6	1.9	1.5	4.3	4.1	4.6	0.5	6.7	
आईआईपी विनिर्माण	3.7	5.8	2.8	4.0	3.1	3.2	3.7	6.0	3.8	5.6	2.0	8.0	
आईआईपी पूंजीगत वस्तुएं	10.5	10.2	8.2	3.6	14.0	13.3	3.0	6.8	4.5	5.4	2.1	10.4	
पीएमआई विनिर्माण	56.4	57.7	56.3	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1	59.3	57.7	59.2	56.6	55.0
पीएमआई निर्यात आदेश	54.7	58.6	56.3	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3	56.1	56.5	54.7	54.1	54.0
पीएमआई विनिर्माण: भविष्य का आउटपुट	62.5	65.1	64.9	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6	60.5	64.8	62.3	57.1	56.9
आठ कोर सूचकांक	5.1	5.1	3.4	4.5	1.0	1.2	2.2	3.7	6.5	3.3	-0.1	2.1	3.7
बिजली उत्पादन: पारंपरिक	4.4	-1.3	2.4	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.8	1.0	0.8	-10.6	-5.0	4.3
बिजली उत्पादन: नवीकरणीय	17.9	31.9	12.2	25.2	28.0	18.2	28.7	26.4	22.7	16.4	21.4	22.9	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	1.3	9.4	2.3	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7	8.1	10.8	-2.8	22.3	37.1
यात्री वाहन उत्पादन	9.2	3.7	4.5	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1	-4.1	16.1	9.8	22.8	23.1
ट्रैक्टर उत्पादन	20.9	23.7	-7.8	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5	9.4	23.0	13.0	37.5	57.9
दोपहिया वाहनों का उत्पादन	-0.6	10.3	1.6	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3	10.0	9.8	-5.6	20.9	39.9
तिपहिया वाहनों का उत्पादन	7.6	16.2	6.5	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0	15.8	15.9	15.9	55.4	39.6
कच्चे इस्पात का उत्पादन	8.3	7.4	6.0	8.5	9.3	11.0	12.6	13.8	12.8	13.7	8.9	10.8	5.3
तैयार इस्पात उत्पादन	5.3	6.7	6.7	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8	13.8	14.0	7.2	11.8	2.0
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	6.0	15.5	-0.5	8.6	24.5	15.7	3.4	13.3	0.2	12.7	8.6	12.8	13.2

<< संकुचन विस्तार >>

टिप्पणी: 1. व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए की गई है।
 2. हीटमैप हर संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा सीरीज की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।
 3. हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
 4. सभी पीएमआई वैल्यू सूचकांक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई वैल्यू >50 का मतलब है 'बढ़ती', <50 का मतलब है 'सिकुड़न' और =50 का मतलब है 'कोई बदलाव नहीं'। PMI हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है। पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं) वैल्यू दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); एसएंडपी वैश्विक; सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए), मिनिस्ट्री ऑफ पावर; सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम); आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार; जॉइंट प्लॉट कमेटी; डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स; और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन।

सारणी III.5: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएँ- विकास दर

संकेतक	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25	अग-25	सित-25	अक्टू-25	नव-25	दिस-25
पीएमआई सेवाएँ	59.3	56.5	59.0	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5	62.9	60.9	58.9	59.8	58.0
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	9.0	11.1	7.7	6.8	13.0	5.0	3.4	5.5	7.7	7.3	9.7	7.5	6.4
घरेलू हवाई माल	4.3	6.9	-2.5	4.9	16.6	2.3	2.6	4.8	7.1	2.8	-2.3	20.5	
अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो	10.5	7.1	-6.3	3.3	8.6	6.8	-1.2	4.2	4.5	2.3	-2.3	12.7	
बंदरगाह कार्गो यातायात	3.5	7.6	3.6	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0	2.5	11.5	11.9	14.5	12.8
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-11.7	8.2	-8.6	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2	8.6	2.7	21.1	17.0	24.6
होटल में रहने वालों की संख्या	-0.2	1.2	0.6	1.9	7.2	-2.8	-0.3	-2.4	-3.2	-0.6	0.0	3.8	
स्टील की खपत	7.7	9.0	10.9	13.6	6.0	8.1	9.3	7.3	10.0	8.9	2.4	6.0	3.4
सीमेंट उत्पादन	10.3	14.3	10.7	12.2	6.3	9.7	8.2	11.6	5.4	5.0	5.2	14.6	13.5

<< संकुचन विस्तार >>

- नोटस:**
- व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए की गई है।
 - हीटमैप हर संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक कलर ग्रेडिएंट स्कीम में बदलता है, जिसमें लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है और हरा रंग संबंधित डेटा सीरीज़ की सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।
 - हीटमैप अप्रैल 2023 से लेकर उस आखिरी महीने तक के डेटा पर लागू होता है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
 - दिसंबर 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात की वृद्धि दर का डेटा प्रतिदिन के डेटा को मिलाकर निकाला जाता है।
 - सभी पीएमआई वैल्यू सूचकांक के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। पीएमआई वैल्यू > 50 का मतलब है बढ़ोतरी, <50 का मतलब है सिकुड़न और = 50 का मतलब है 'कोई बदलाव नहीं'। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग सबसे कम वैल्यू दिखाता है, पीला रंग 50 (या कोई बदलाव नहीं वैल्यू) दिखाता है, और हरा रंग हर पीएमआई सीरीज़ में सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाता है।

स्रोत: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए): इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया: जॉइंट प्लांट कमेटी: ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर; और एसएंडपी वैश्विक।

इसके अतिरिक्त, सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास विधेयक (शांति विधेयक²², 2025 और परमाणु ऊर्जा मिशन के लागू होने से 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावॉट तक पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही नियामक निगरानी के तहत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी भी संभव हो सकेगी।

सेवाओं की गतिविधि के मासिक संकेतक

दिसंबर में भारत के सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी रहा। माल की आवाजाही में सुधार और अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि के कारण खुदरा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी गई। बंदरगाह माल यातायात ने भी वृद्धि की गति को बनाए रखा [सारणी III.5]।

मुद्रास्फीति

हेडलाइन मुद्रास्फीति²³ में दिसंबर में लगातार दूसरे महीने वृद्धि हुई, जबकि अक्टूबर में यह मौजूदा सीपीआई शृंखला

(2012=100) के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। खाद्य समूहों में अपस्फीति की दर में कमी और कोर (अर्थात् खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण दिसंबर में यह बढ़कर 1.3 प्रतिशत हो गई [चार्ट III.9]²⁴

खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार चौथे महीने भी अवमूल्यन की श्रेणी में रहीं, हालांकि अवमूल्यन की दर में कमी आई²⁵ खाद्य समूहों के भीतर, अनाज, दालें, मसाले और सब्जियों की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गिरावट आई। फलों, गैर-मादक पेय पदार्थों, तैयार भोजन और तेल एवं वसा जैसे उप-समूहों में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि अंडे, मांस और मछली, दूध और उत्पाद तथा चीनी में मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ गई (चार्ट III.10)।

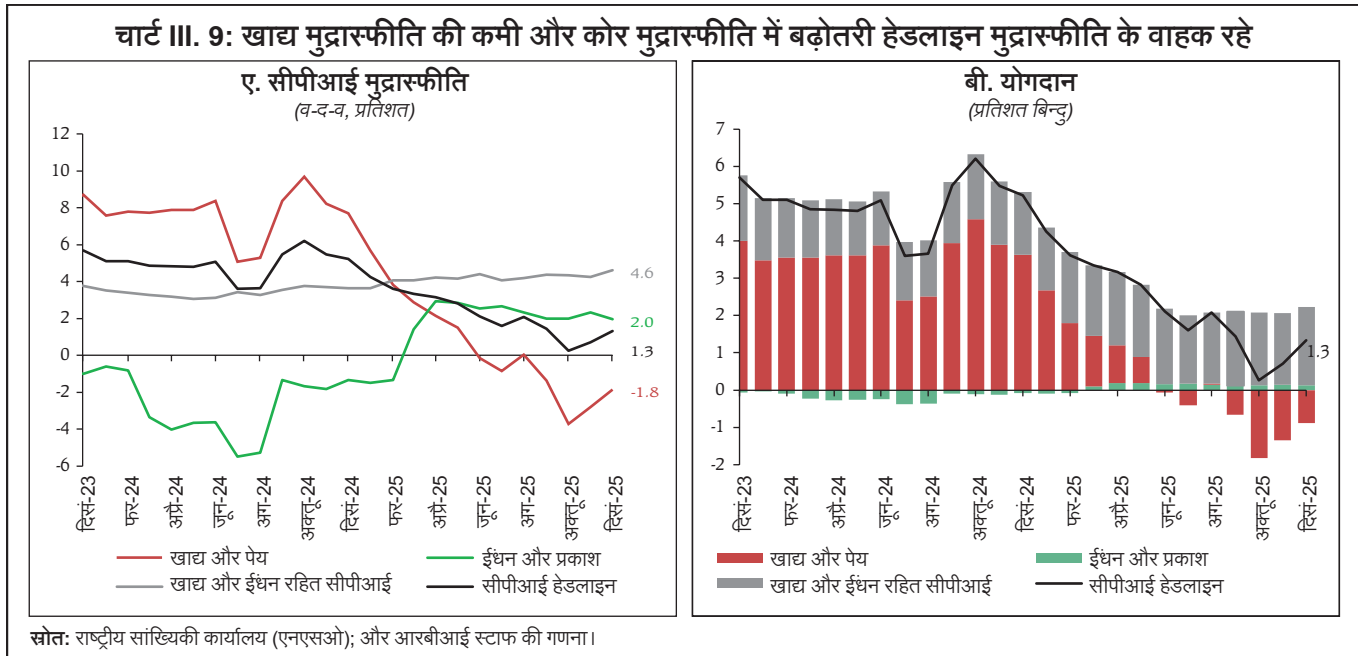
ईंधन और प्रकाश की मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 2.0 प्रतिशत हो गई, जो नवंबर में 2.3 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण अनुकूल आधार प्रभाव था। केरोसिन-पीडीएस और एलपीजी की मुद्रास्फीति में कमी इसका प्रमुख कारण रही।

²² <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=156593&NoteId=156593&ModuleId=3@=3&lang=2>

²³ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 जनवरी 2026 को जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार।

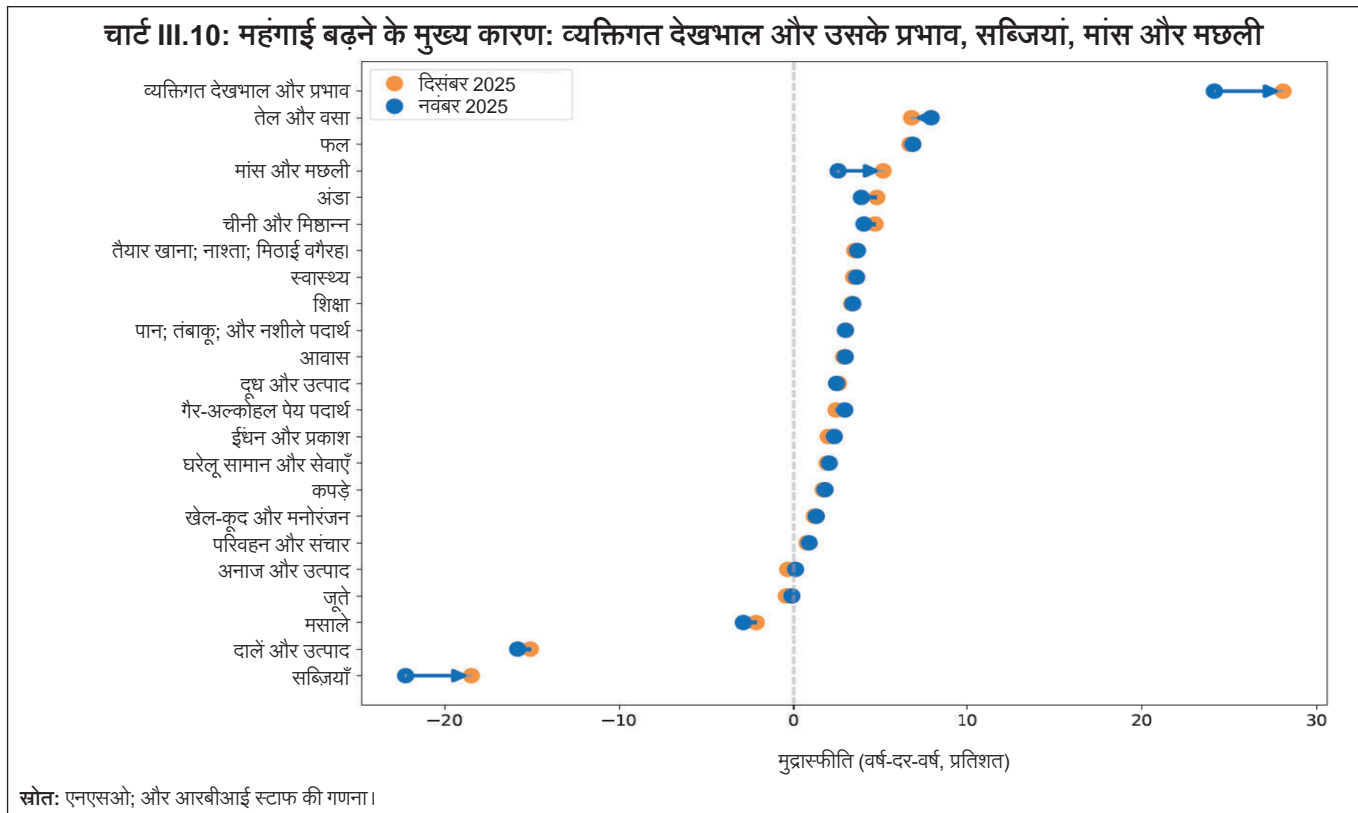
²⁴ 60 बीपीएस तक की मुद्रास्फीति में वृद्धि 55 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव के साथ-साथ 5 बीपीएस की सकारात्मक कीमत गति के कारण थी।

²⁵ खाद्य अपस्फीति दिसंबर में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले माह में 2.8 प्रतिशत थी।



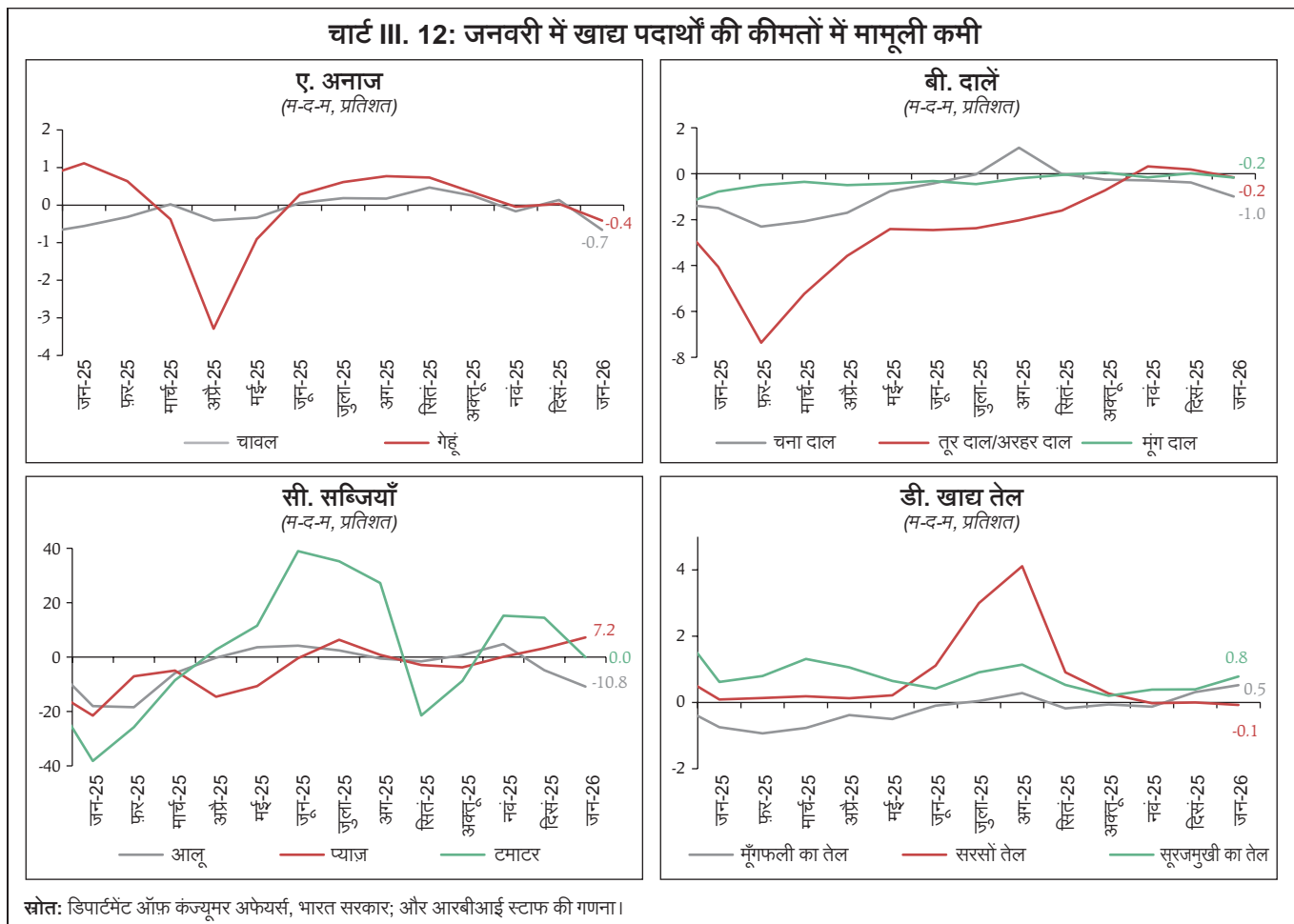
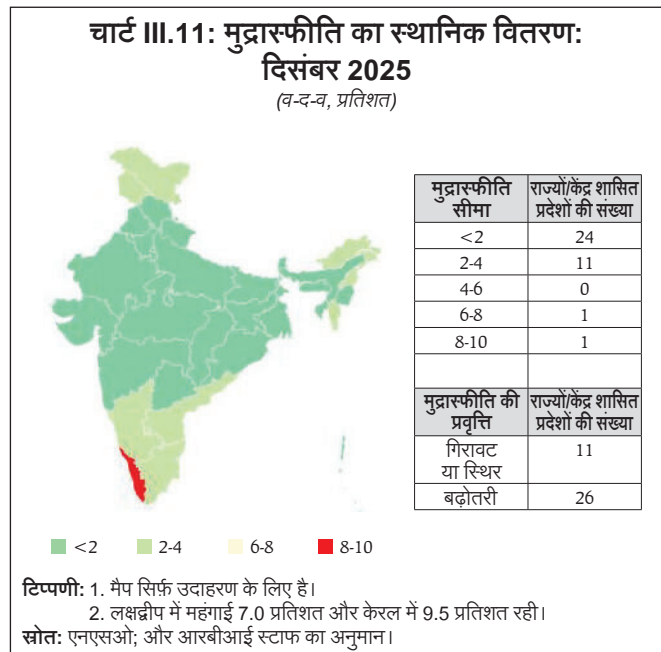
दिसंबर में कोर मुद्रास्फीति पिछले माह के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई। कपड़ों और जूतों, स्वास्थ्य, घरेलू सामान और सेवाओं, परिवहन और संचार, आवास, मनोरंजन और शिक्षा आदि क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में कमी आई, जबकि स्वर्ण

की बढ़ती कीमतों के कारण व्यक्तिगत देखभाल और सामान के क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़ गई। कीमती धातुओं को छोड़कर, दिसंबर में कोर मुद्रास्फीति 2.3 प्रतिशत रही, जो नवंबर के समान ही थी।



भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, दिसंबर में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में मजबूती आई²⁶ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति (-) 4.2 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत तक भिन्न रही, अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से नीचे बनी रही। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति में व्यापक वृद्धि देखी गई, जिसमें 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.11)।

जनवरी के अब तक के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आंकड़ों (19 तारीख तक) से अनाज की कीमतों में नरमी के संकेत मिलते हैं। दालों में, चना, मूंग और तुअर/अरहर दाल की कीमतों में व्यापक रूप से नरमी देखी गई है। खाद्य तेलों में, सूरजमुखी तेल और मूंगफली तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। सब्जियों में, प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई जबकि आलू की कीमतों में और गिरावट आई (चार्ट III.12)।



²⁶ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति क्रमशः 2.0 और 0.8 प्रतिशत रही।

सारणी III.6: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		Jan-25	Dec-25	Jan-26 ^	Dec-25	Jan-26 ^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.0	101.1	101.2	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.5	90.5	90.5	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी)	₹/लीटर	43.9	48.6	45.1	5.9	-7.4
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.3	863.3	863.3	0.0	0.0

^ : 1-19 जनवरी, 2026 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ की गणना।

जनवरी 2026 (19 तारीख तक) में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन की कीमतों में गिरावट आई (सारणी III.6)।

दिसंबर में, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के पीएमआई में इनपुट कीमतों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई। विनिर्माण

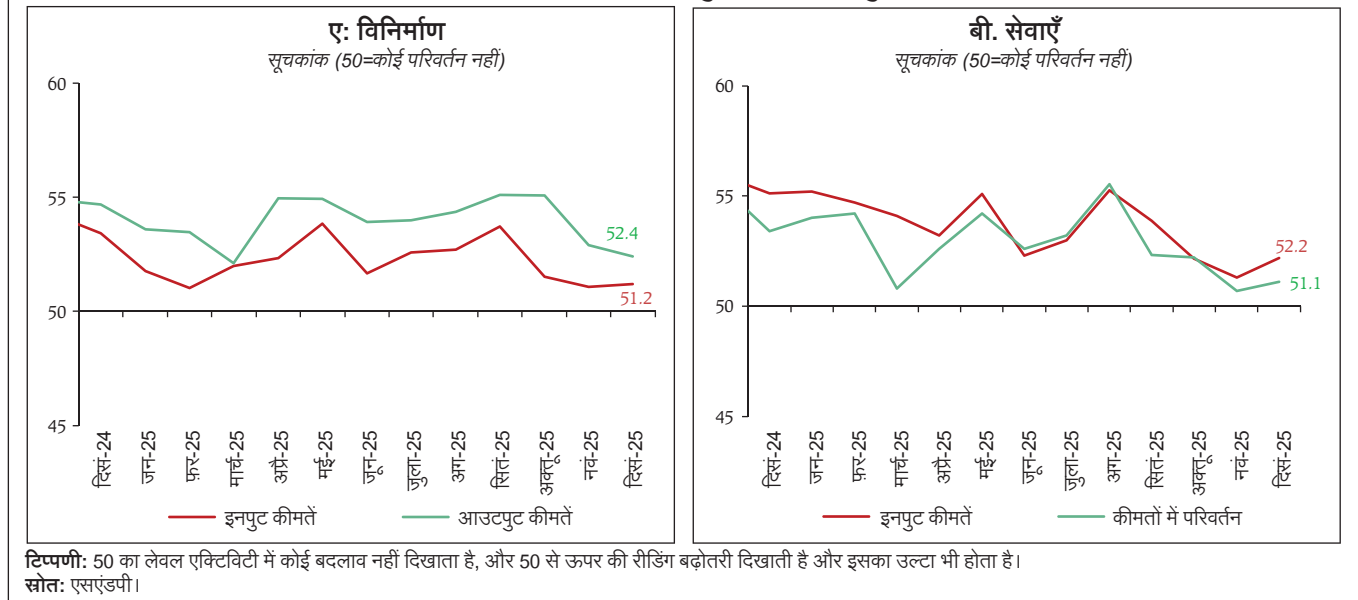
कंपनियों के लिए आउटपुट मूल्य मुद्रास्फीति में नरमी आई, जबकि सेवाओं के लिए इसमें वृद्धि हुई (चार्ट III.13)।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

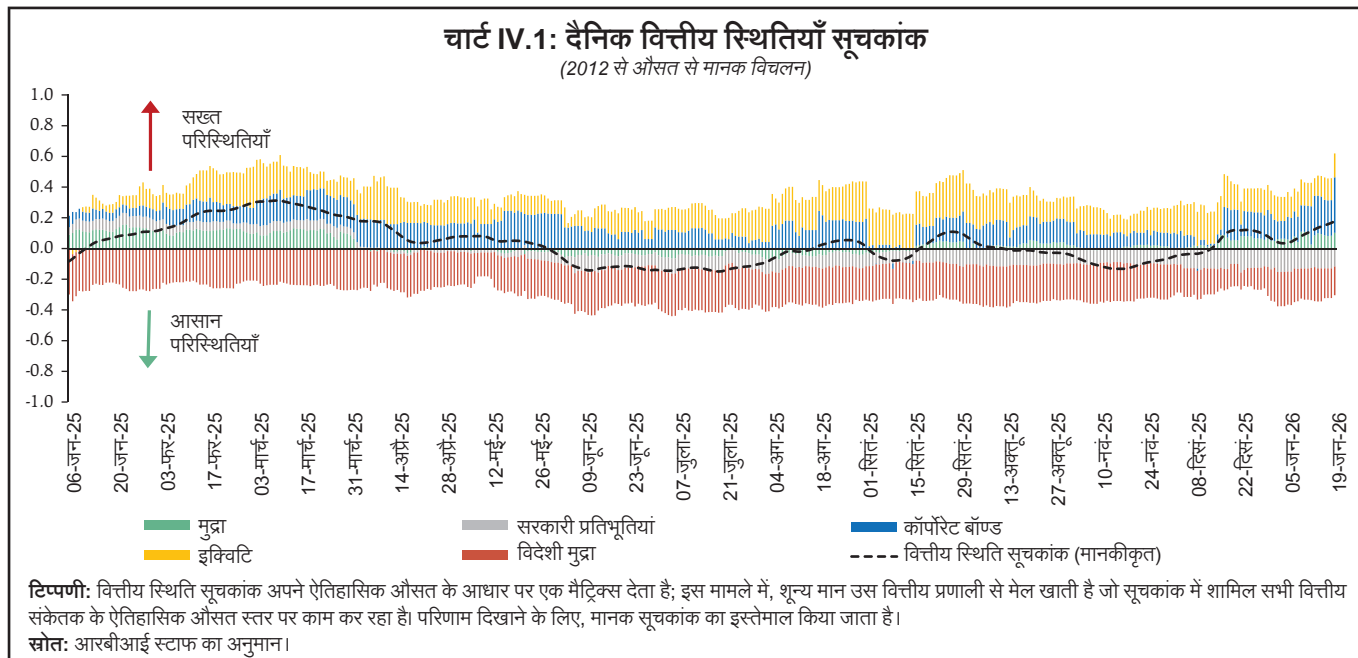
दिसंबर के उत्तरार्ध से वित्तीय स्थितियों में दोतरफा उतार-चढ़ाव देखने को मिला (चार्ट IV.1)।

दिसंबर के उत्तरार्ध में, अग्रिम कर और जीएसटी संबंधी भुगतानों के परिणामस्वरूप सरकारी नकदी शेष में वृद्धि के कारण बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि अधिशेष से घाटे में बदल गई। इस अस्थायी चलनिधि संकट को दूर करने के लिए, रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की।²⁷ रिजर्व बैंक ने ₹2 लाख करोड़ की खरीद नीलामी और 10 अरब अमेरिकी डॉलर की 3-वर्षीय यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी सहित नए खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) की भी घोषणा की।²⁸ दिसंबर के अंत से जनवरी (19 तारीख तक) तक, सरकारी व्यय में तेजी और आरबीआई के स्थायी चलनिधि परिचालन के परिणामस्वरूप प्रणाली की चलनिधि फिर से अधिशेष में बदल गई।

चार्ट III. 13: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



²⁷ दिसंबर की दूसरी छमाही और जनवरी में (19 जनवरी तक) आरबीआई ने एकदिवसीय और 10 दिन की परिपक्वता तक की 21 वीआरआर नीलामी आयोजित की।
²⁸ भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 दिसंबर 2025, 05 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली 0.5 लाख करोड़ रुपये की चार किशतों में कुल 2 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद नीलामी की घोषणा की। कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की ओएमओ खरीद की पहली तीन किशतों के लिए नीलामी पहले ही आयोजित की जा चुकी है, जिसमें अच्छी मांग देखी गई है। 13 जनवरी 2026 को आयोजित 3 वर्षों की अवधि के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खरीद/बिक्री की स्वैप नीलामी में अधिसूचित राशि से लगभग तीन गुना अधिक बोलियाँ रहीं।

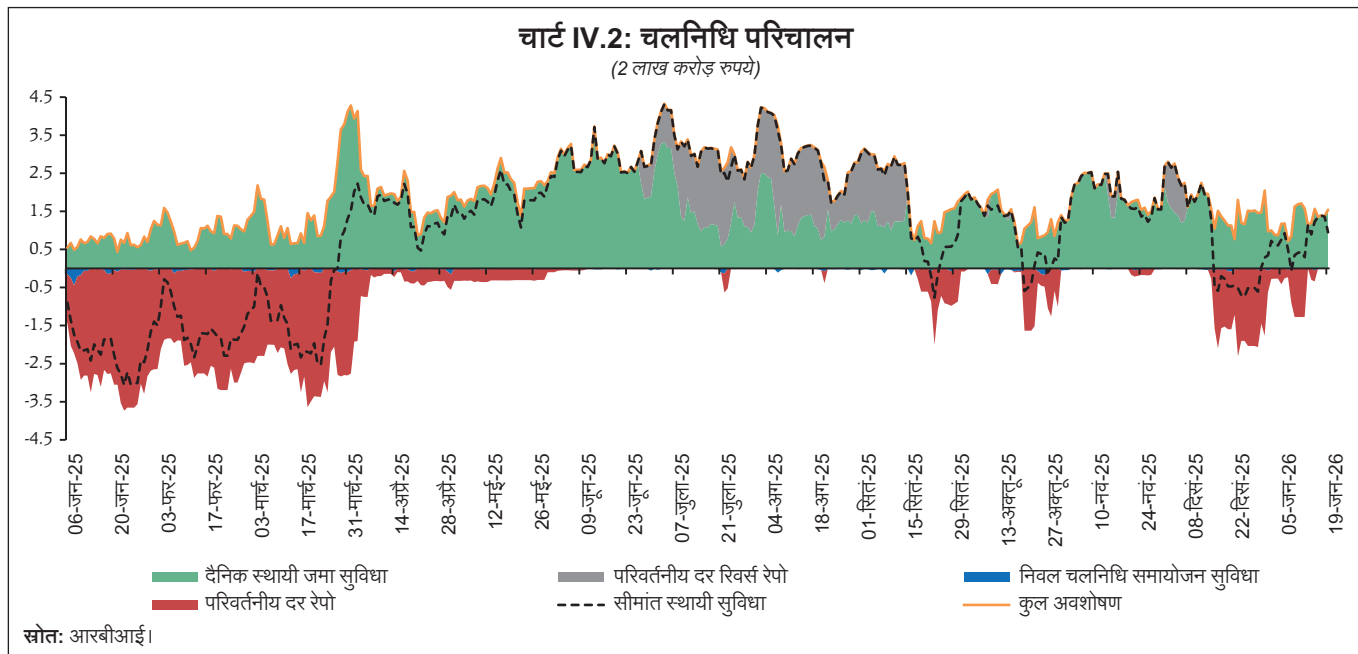


कुल मिलाकर, 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत निवल अवशोषण ₹0.21 लाख करोड़ रहा, जबकि इससे पहले की एक माह अवधि में निवल अवशोषण ₹1.90 लाख करोड़ था (चार्ट IV.2)। स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत शेष राशि में गिरावट

आई, और सीमांत स्थायी सुविधा में बैंकों का सहारा मामूली रूप से बढ़ा²⁹

मुद्रा बाज़ार

भारत औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) आम तौर पर दिसंबर और जनवरी (19 जनवरी तक) के दौरान नीतिगत



²⁹ स्थायी जमा सुविधा के तहत औसत शेष राशि 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 के दौरान घटकर 1.31 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले एक माह की अवधि में 1.69 लाख करोड़ रुपये थी। इस अवधि के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा से औसतन 0.018 लाख करोड़ रुपये की उधारी हुई, जो पिछले एक महीने की अवधि में 0.017 लाख करोड़ रुपये थी।

दायरे में बनी रही। दिसंबर और जनवरी के उत्तरार्ध (19 जनवरी तक) में यह नीतिगत रेपो दर से ऊपर रही। 31 दिसंबर को, तिमाही के अंत में सामान्य सख्ती और पाक्षिक रिज़र्व रखरखाव आवश्यकताओं के कारण यह एमएसएफ दर से ऊपर चढ़ गई। औसतन, 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 के दौरान डबल्यूएसीआर पिछली एक माह अवधि की तुलना में 5.4 प्रतिशत अधिक थी (चार्ट IV.3ए) संपार्श्विकित खंडों में एकदिवसीय दरें बेंचमार्क प्रतिभूतित एकदिवसीय रुपया दर (एसओआरआर) द्वारा मापी गई – गैर-संपार्श्विकित दर के अनुरूप रहीं। इस अवधि के दौरान तीन महीने के ट्रेजरी बिलों पर औसत प्रतिफल कम रहा, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए तीन महीने के वाणिज्यिक पत्रों पर प्रतिफल में मामूली वृद्धि हुई। ऋण वृद्धि में तेजी के बीच आपूर्ति में अपेक्षित वृद्धि के कारण तीन महीने के जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज दर में भी मामूली वृद्धि हुई (चार्ट IV.3बी)।³⁰ मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 माह के वाणिज्यिक पत्र और

91 दिन के ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल के बीच का अंतर) में वृद्धि देखी गई।³¹

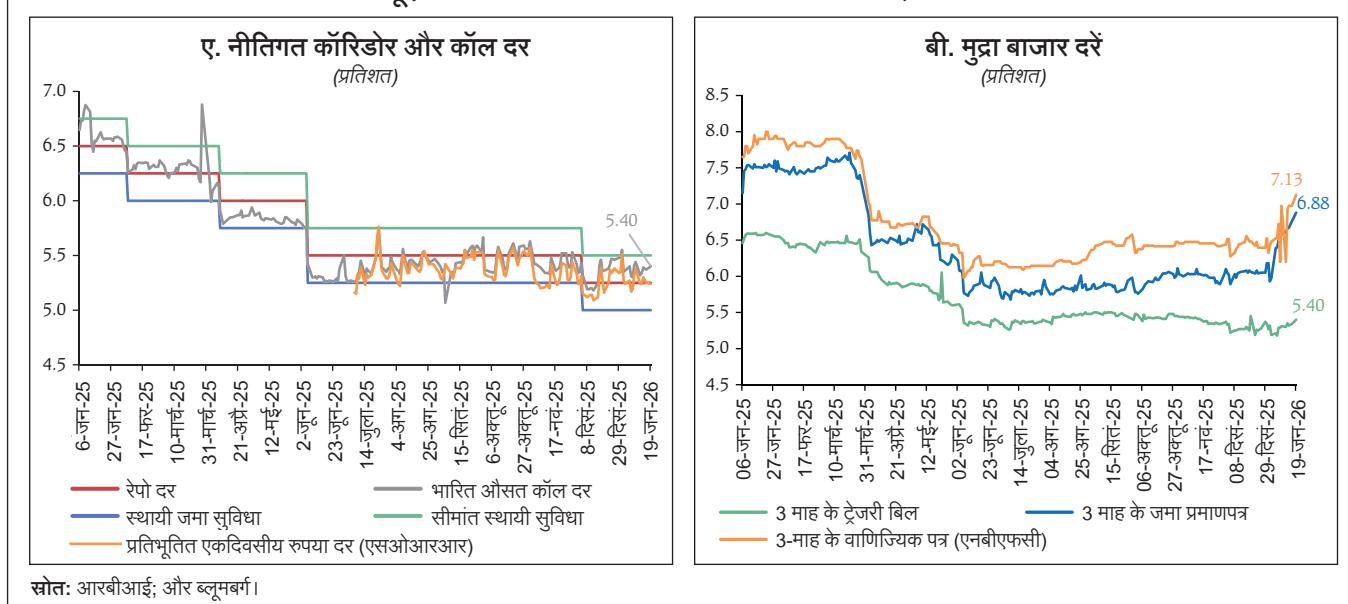
सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

निर्धारित आय वाले भाग में, दिसंबर और जनवरी के अधिकांश समय (19 तारीख तक) के लिए जी-सेक प्रतिफल में बढ़ोतरी आई है, जबकि बाजार में दरों में और कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं। हालांकि, 23 दिसंबर 2025 को रिज़र्व बैंक द्वारा ओएमओ खरीद की घोषणा के बाद एक संक्षिप्त कमी आई (चार्ट IV.4ए)।³² 16 दिसंबर 2025 की तुलना में प्रतिफल वक्र (19 जनवरी, 2026 तक) अवधि भर में बढ़ गया है (चार्ट IV.4बी)।

कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार

कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल अवधि और रेटिंग स्पेक्ट्रम में कठोर हो जाती है। नतीजतन, सरकारी प्रतिभूतियों पर उनका

चार्ट IV.3: डबल्यूएसीआर का नीतिगत रेपो दर से ऊपर व्यापार, अल्पकालिक उच्च दरें

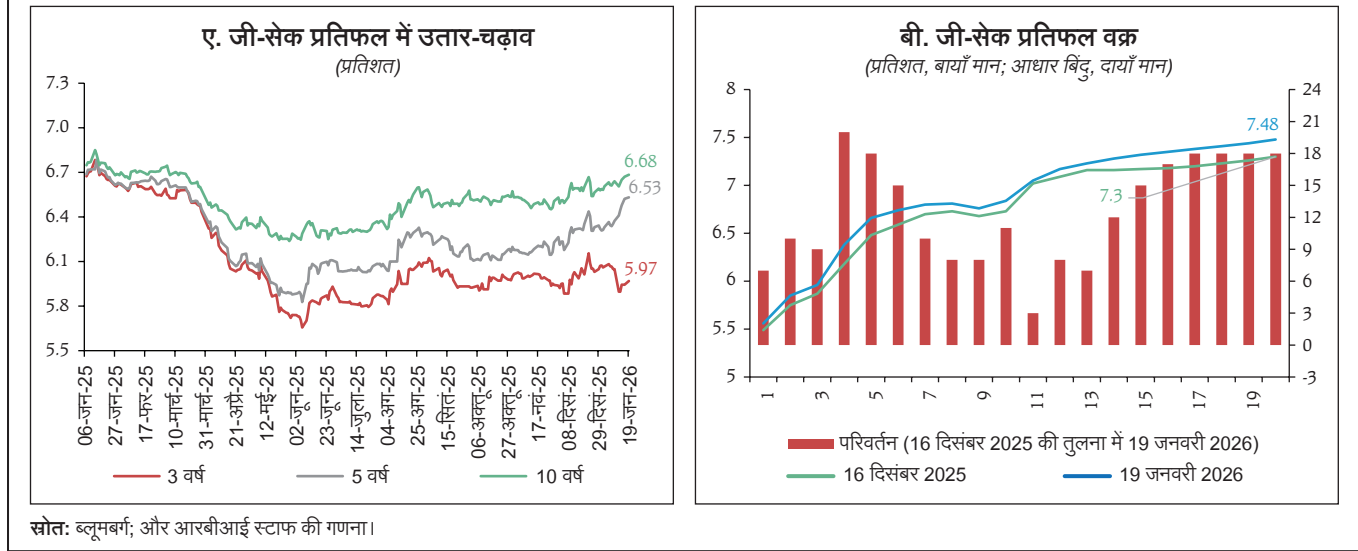


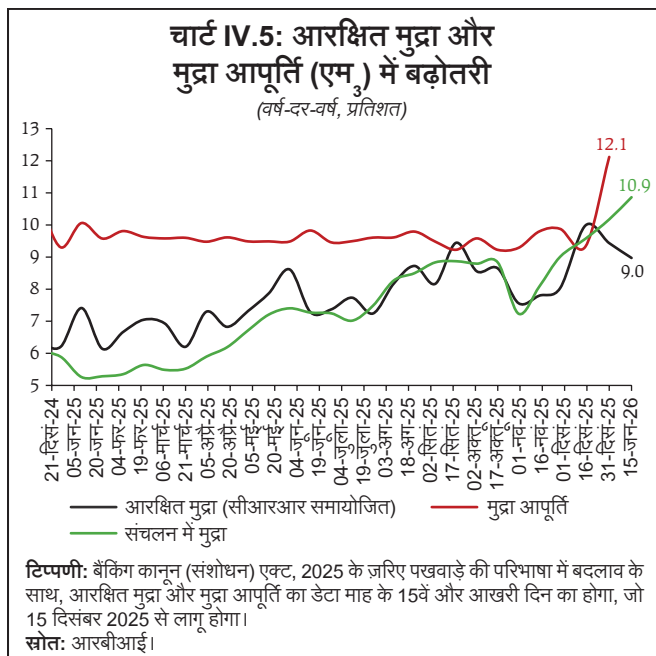
³⁰ 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2026 तक की अवधि की तुलना में 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 के दौरान 3-माह के वाणिज्यिक पत्रों और एनबीएफसी द्वारा जारी 3-माह के वाणिज्यिक पत्रों और 3-माह के जमा प्रमाणपत्र पर प्रतिफल क्रमशः 14 बीपीएस और 30 बीपीएस तक अधिक हो गया।

³¹ 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक की अवधि के दौरान 127 बीपीएस तक बढ़ गया, जो पिछले एक महीने की अवधि में 111 बीपीएस था।

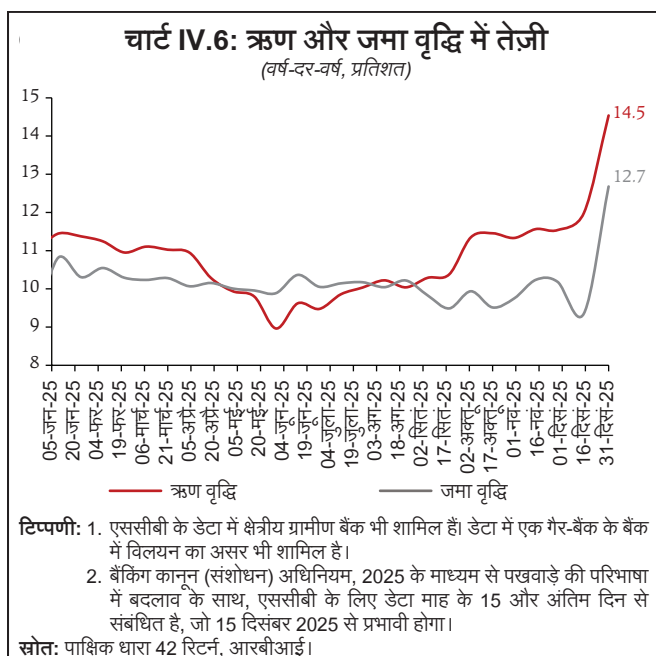
³² 23 दिसंबर 2025 को 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त ओएमओ खरीद की घोषणा के बाद, 3, 5 और 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 23 से 24 दिसंबर 2025 के दौरान उनके पूर्व-घोषणा स्तरों से 10 बीपीएस से अधिक हो गया।

चार्ट IV.4: जी-सेक प्रतिफल में बढ़ोतरी





वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक (31 दिसंबर तक), वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह एक वर्ष पहले के ₹21.3 लाख करोड़ से बढ़कर ₹30.8 लाख करोड़ हो गया है (सारणी IV.2ए)। गैर-बैंक स्रोतों - कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - में इस वर्ष अब तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 31 दिसंबर 2025 तक,



वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया ऋण में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें गैर-बैंक स्रोतों में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी IV.2बी)।

सारणी IV.2ए: वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ लाख करोड़)

स्रोत	अप्रैल-मार्च		31 दिसंबर तक	
	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26 पी
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	21.40	17.98	12.78	20.27
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	12.64	17.10	8.55	10.58
बी1. घरेलू स्रोत	10.20	13.86	6.43	7.66
बी2. विदेशी स्रोत	2.43	3.25	2.12	2.92
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	34.04	35.09	21.32	30.85

पी: अनंतिमा

टिप्पणियाँ: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण आकड़ों का योग भिन्न हो सकता है।
2. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (ए) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

सारणी IV.2बी: वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बकाया ऋण

(₹ लाख करोड़; कोष्ठक में आंकड़े व-द-व प्रतिशत परिवर्तन हैं)

स्रोत	मार्च के अंत में		31 दिसंबर तक	
	2024	2025	2024	2025 P
ए. गैर-खाद्य बैंक ऋण	164.09	182.07	176.87	202.35
	(20.2)	(11.0)	(11.1)	(14.4)
बी. गैर-बैंक स्रोत (बी1+बी2)	77.56	88.85	82.14	95.58
	(4.2)	(14.6)	(11.7)	(16.4)
बी1. घरेलू स्रोत	56.59	66.37	60.21	71.62
	(4.9)	(17.3)	(14.8)	(18.9)
बी2. विदेशी स्रोत	20.97	22.48	21.93	23.96
	(2.4)	(7.2)	(4.2)	(9.2)
सी. कुल ऋण (ए+बी)	241.65	270.93	259.01	297.93
	(14.5)	(12.1)	(11.3)	(15.0)

पी: अनंतिमा

टिप्पणियाँ: 1. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण आकड़ों का योग भिन्न हो सकता है।
2. गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के तहत इक्विटी और हाइब्रिड लिखत जारी किए जाने और विदेशी स्रोतों के तहत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं है।
3. बकाया डेटा के आधार पर प्रवाह सारणी IV.2ए में प्रदान किए गए प्रवाह के साथ मेल नहीं खा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित हो सकता है:
(ए) 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का विलय;
(बी) कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में परिवर्तन; और
(सी) विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
4. विस्तृत नोट्स और डेटा के लिए, कृपया वर्तमान सांख्यिकी सारणी संख्या: 18 (बी) देखें।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई कर्मचारियों का अनुमान।

कुल मिलाकर, गैर-खाद्य बैंक ऋण³⁷ वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) नवंबर में काफी हद तक मजबूत रही (चार्ट IV.7)। औद्योगिक ऋण वृद्धि में मामूली कमी आई है, बड़े उद्योगों को ऋण स्थिर बना हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) नवंबर में दोहरे अंकों में बनी रही। सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में पिछले माह की तुलना में मध्यम गति से दहाई अंकों की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई, हालांकि यह मध्यम गति से है। सेवा क्षेत्र में, हालांकि एनबीएफसी को बैंक ऋण देने में कमी आई है, लेकिन व्यापार जैसे क्षेत्र उत्साहजनक बने हुए हैं। व्यक्तिगत ऋण में वृद्धि नरम हो गई,

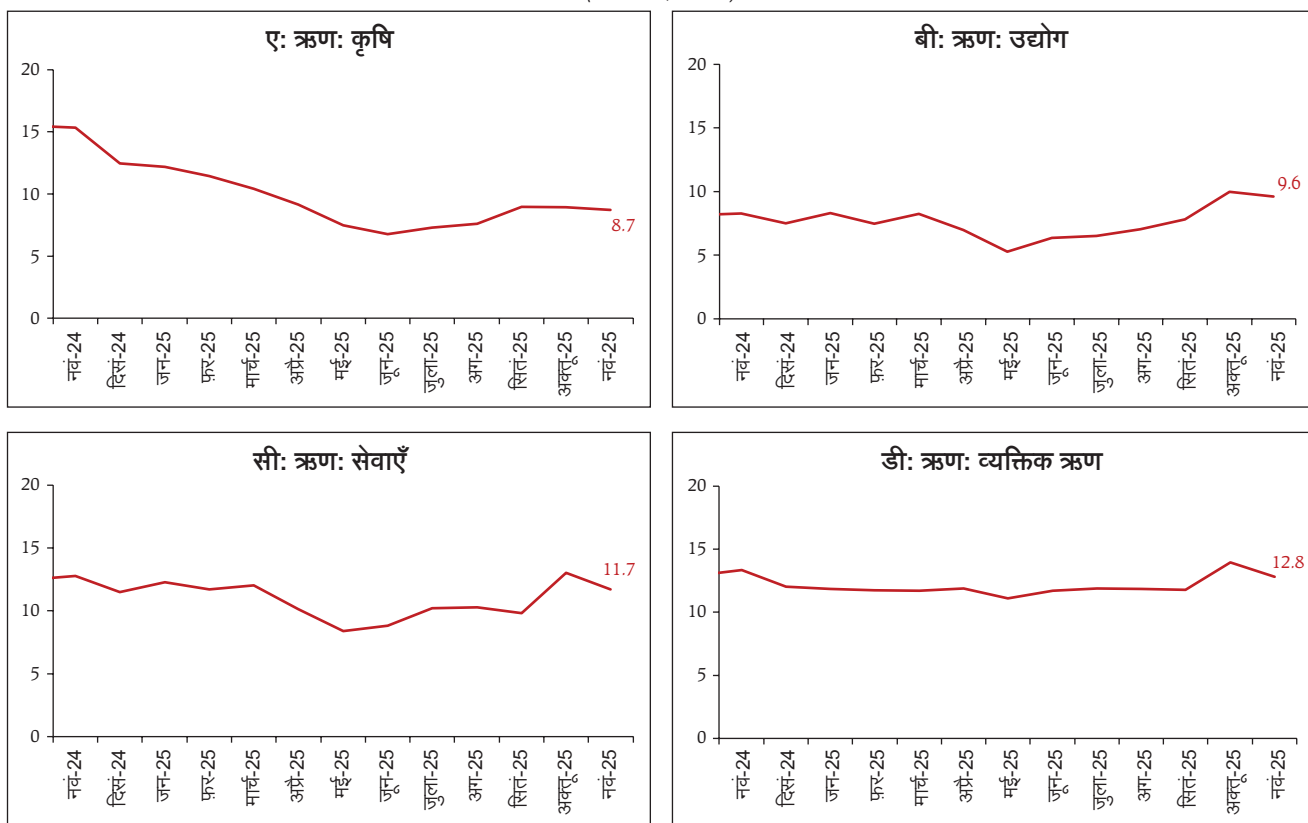
जो मुख्य रूप से आवास और क्रेडिट कार्ड क्षेत्रों में मंदी के कारण प्रेरित थी। हालांकि, वाहन ऋण में लगातार विस्तार जारी रहा।

जमा और उधार दरें

फरवरी-नवंबर 2025 के दौरान नीतिगत रेपो दर में संचयी 100 आधार अंकों की कमी के जवाब में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंकड बाहरी बेंचमार्क-आधारित ऋण दरों (ईबीएलआर) को उसी परिमाण से कम कर दिया। बैंकों की सीमांत लागत आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में भी कमी आई। इस अवधि के दौरान नए और बकाया दोनों रुपये के ऋणों पर भारित

चार्ट IV.7: बैंक ऋण काफी हद तक मजबूत बना रहा

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई।

³⁷ अनंतिम डेटा। गैर-खाद्य ऋण डेटा आरबीआई की पाक्षिक धारा-42 रिटर्न पर आधारित है। क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होता है, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत चुनिंदा बैंकों को कवर करता है। एसआईबीसी रिटर्न के तहत कवर किए गए बैंक समूह हैं - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक। डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी IV.3: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		ऋण दरें				
		डबल्यूएलटीडीआर- नया जमा	डबल्यूएलटीडीआर - बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डबल्यूएलआर – नया रुपया ऋण		डबल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण
						कुल	ब्याज दर प्रभाव [#]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख्ती की अवधि मई 2022 से जन 2025 तक	250	259	206	250	175	182	191	115
सहजता चरण फर 2025 से नव 2025	-100	-103	-36	-100	-50	-62	-82	-66

#: जनवरी 2025 से भार की पर गणना की गई।

डबल्यूएलआर: भारत औसत ऋण दर; डबल्यूएलटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर।

एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य बैंचमार्क-आधारित उधार दर।

टिप्पणी: ईबीएलआर पर आंकड़े 32 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।

स्रोत: आरबीआई।

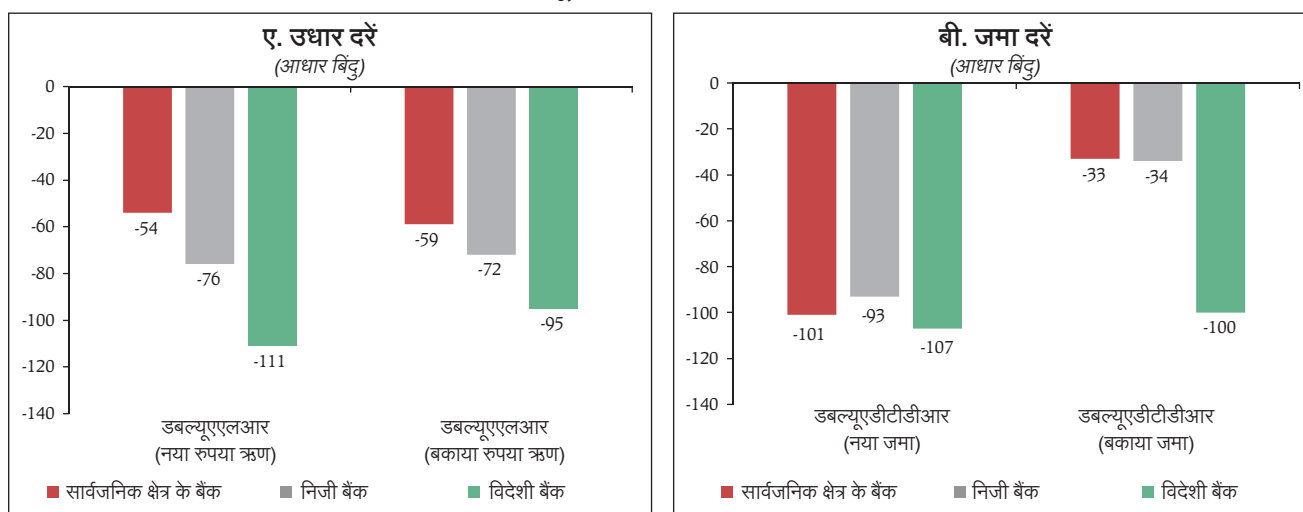
औसत ऋण दरों में गिरावट आई। जमा पक्ष में, बैंकों ने नई सावधि जमा पर ब्याज दरों में काफी कटौती की है। बकाया जमाराशियों पर ब्याज दरों का प्रभाव-अंतरण धीरे-धीरे था, जो निश्चित दरों पर सावधि जमा की लंबी अवधि के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी IV.3)।

नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारत औसत ऋण दर में गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंकों के मामले में अधिक थी (चार्ट IV.8)। जमा पक्ष पर, नई सावधि

जमाओं के मामले में निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संचरण अधिक था।

केंद्र सरकार ने विभिन्न लघु बचत साधनों पर ब्याज दरों की समीक्षा की, जो तुलनीय परिपक्वता के जी-सेक पर द्वितीयक बाजार के प्रतिफल से जुड़ी हैं और उन्हें 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा गया है। इन साधनों पर प्रचलित दरें उनकी फॉर्मूला-आधारित दरों से अधिक हैं।

चार्ट IV.8: बैंक समूहों में संचरण (फरवरी - नवंबर 2025)



टिप्पणी: फरवरी से नवंबर 2025 के दौरान संचरण की गणना जनवरी 2025 की भारत औसत उधार और जमा दरों को नवंबर की भारत औसत दर से घटाकर की जाती है।

स्रोत: आरबीआई।

इक्विटी बाजार

भारतीय इक्विटी बाजारों ने दिसंबर 2025 में भारत-अमेरिका व्यापार सौदे और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यहास के बारे में सावधानी के बीच द्विदिशात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की नीतिगत दर में कटौती, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के समापन और नए सिरे से एआई आशावाद सहित सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने समर्थन प्रदान किया। मजबूत जीडीपी वृद्धि, वैश्विक धातु की बढ़ती कीमतों और सरकार द्वारा चुनिंदा इस्पात आयात पर तीन वर्ष का सुरक्षा शुल्क लगाने के कारण धातु क्षेत्र में अधिकतम लाभ दर्ज किया गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा लगातार बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) द्वारा मजबूत खरीद ने इक्विटी बाजारों को कुछ समर्थन प्रदान किया (चार्ट IV.9)। जनवरी 2026 (19 तारीख तक) में, इक्विटी बाजारों में अमेरिका द्वारा नई टैरिफ चेतावनियों के मद्देनजर नए सिरे से नीचे की ओर दबाव देखा गया।

वित्त के बाह्य स्रोत

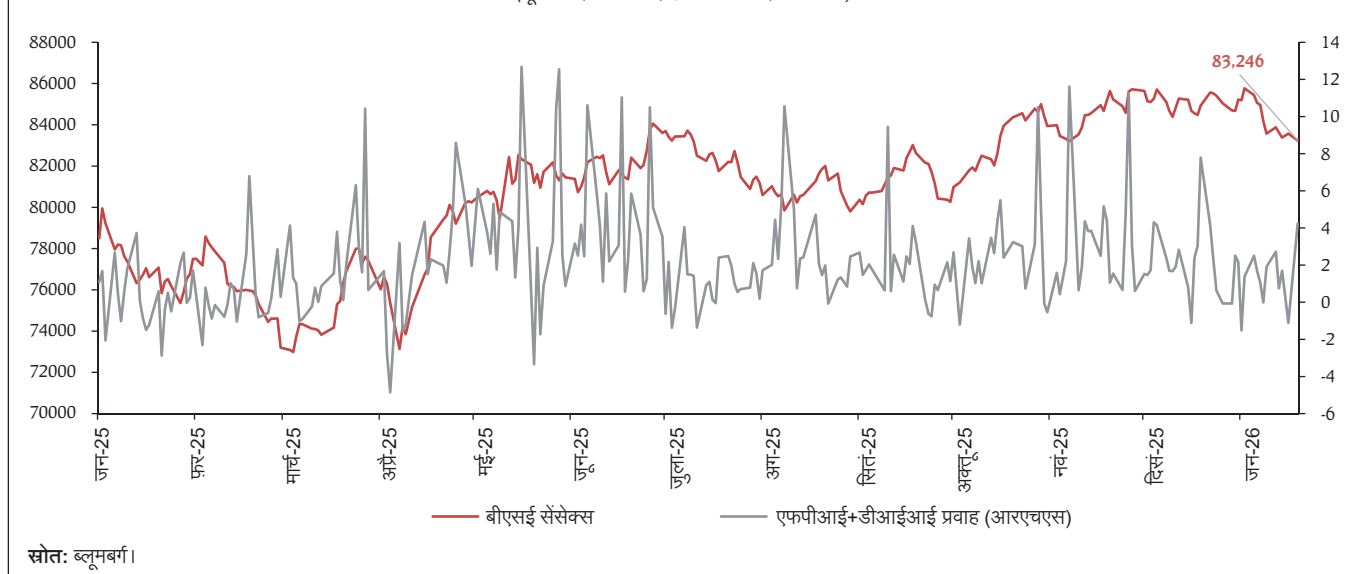
अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सकल और निवल दोनों रूपों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा। नवंबर में सकल आवक

एफडीआई स्थिर रहा और कुल एफडीआई प्रवाह में जापान, सिंगापुर और अमेरिका की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक रही। एफडीआई प्रवाह में सबसे अधिक प्राप्तकर्ता (लगभग 75 प्रतिशत) वित्तीय सेवा क्षेत्र थे, इसके बाद विनिर्माण, खुदरा और थोक व्यापार थे। हालांकि, निवल एफडीआई नवंबर में लगातार तीसरे महीने ऋणात्मक रहा, जिसका मुख्य कारण उच्च प्रत्यावर्तन है। नवंबर में बाह्य एफडीआई में कमी आई, जिसमें सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका और यूके का कुल बाह्य एफडीआई में आधे से अधिक हिस्सा था (चार्ट IV.10)। क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण से पता चलता है कि 70 प्रतिशत से अधिक बाह्य एफडीआई विनिर्माण, वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाओं में था।

वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक (16 जनवरी तक), निवल एफपीआई ने बहिर्वाह दर्ज किया है, जो इक्विटी सेगमेंट द्वारा संचालित है।³⁸ भारत-अमेरिका व्यापार सौदे के आसपास की अनिश्चितता और रुपये के कमजोर होने ने हाल के महीनों में भारत में निवल एफपीआई प्रवाह को शांत रखा है (चार्ट IV.11)। अक्टूबर और नवंबर में निवल प्रवाह के एक संक्षिप्त चरण के बाद, एफपीआई ने दिसंबर में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया। पांच महीने की अवधि के बाद दिसंबर में ऋण प्रवाह भी ऋणात्मक हो गया।

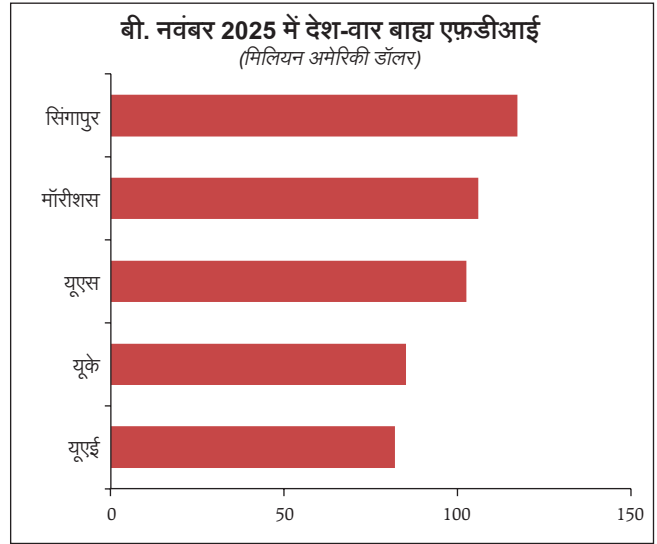
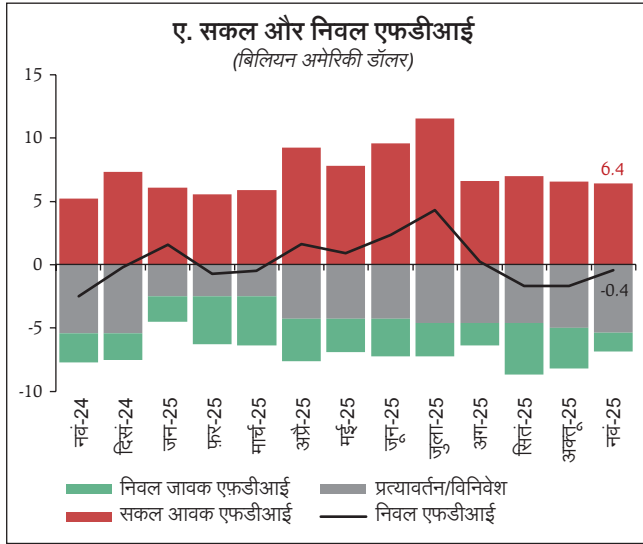
चार्ट IV.9: दिसंबर में घरेलू इक्विटी बाजार में दोनों तरफ से उतार-चढ़ाव

(सूचकांक, बायां मान; ₹ हजार करोड़, दायां मान)



³⁸ वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक (16 जनवरी 2026 तक) 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई बहिर्वाह हुआ है।

चार्ट IV. 10: स्थिर सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह



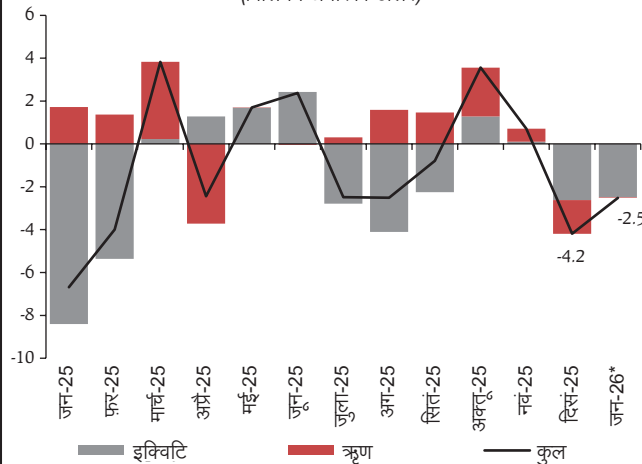
स्रोत: आरबीआई।

अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का पंजीकरण और निवल प्रवाह एक वर्ष पहले की समान अवधि की तुलना में कम हो गया, जो अपतटीय धन उगाहने की गतिविधि में व्यापक मंदी को दर्शाता है (चार्ट IV.12)³⁹ इसीबी

फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा⁴⁰ पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए जुटाया गया था।

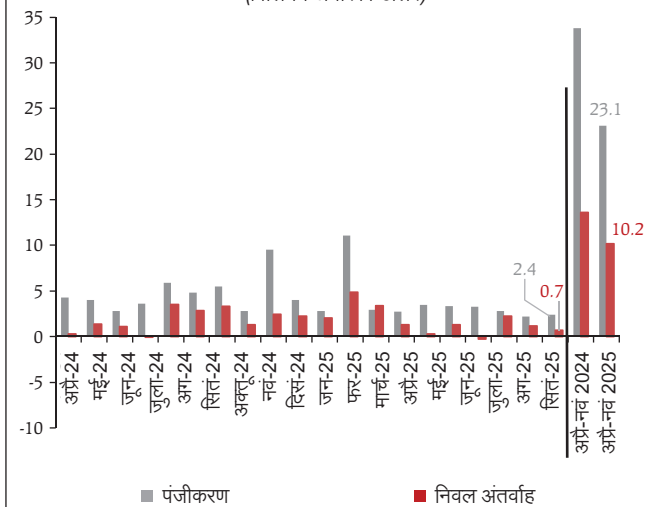
भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सहनीय बना हुआ है, जैसा कि सितंबर 2025 के अंत तक नवीनतम प्रमुख बाहरी भेद्यता

चार्ट IV.11: दिसंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



*: 16 जनवरी 2026 तक का डेटा।
टिप्पणी: ऋण में हाइब्रिड लिखत के तहत निवेश शामिल हैं।
स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

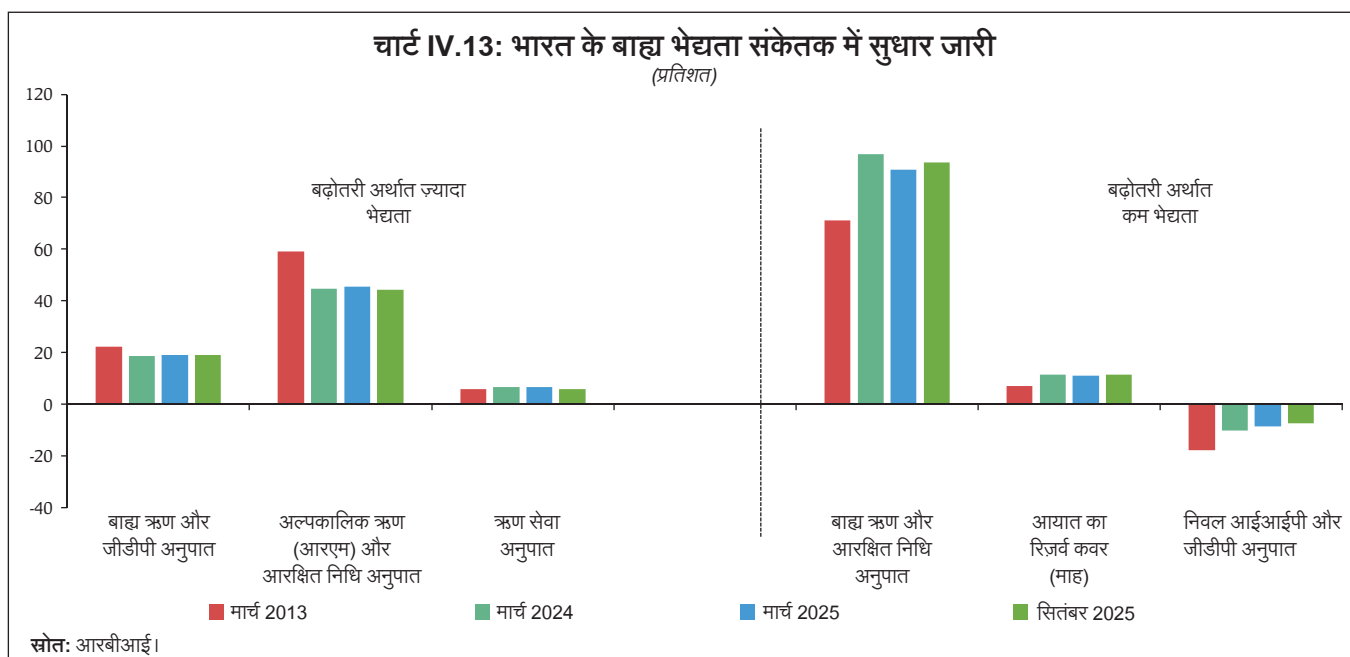
चार्ट IV.12: बाह्य वाणिज्यिक उधार – पंजीकरण और प्रवाह में कमी
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



स्रोत: आरबीआई।

³⁹ अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधारों का पंजीकरण घटकर 23.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले की इसी अवधि में 33.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

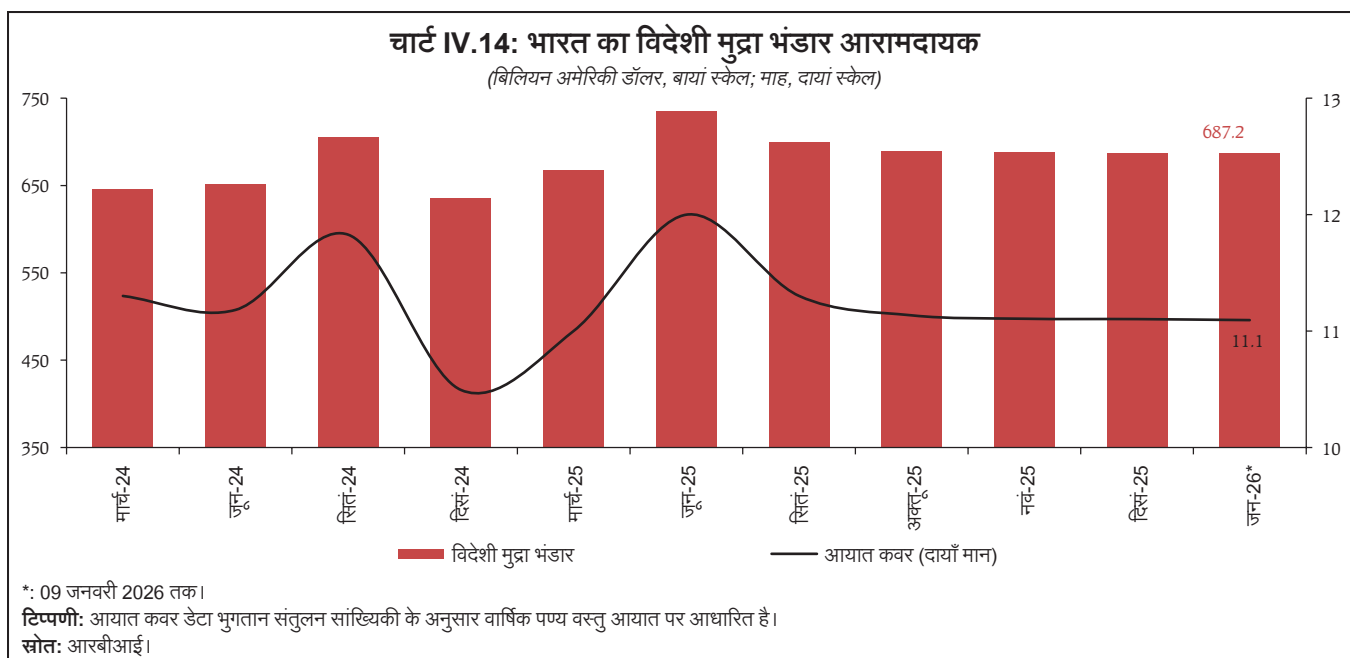
⁴⁰ लगभग 43 प्रतिशत।



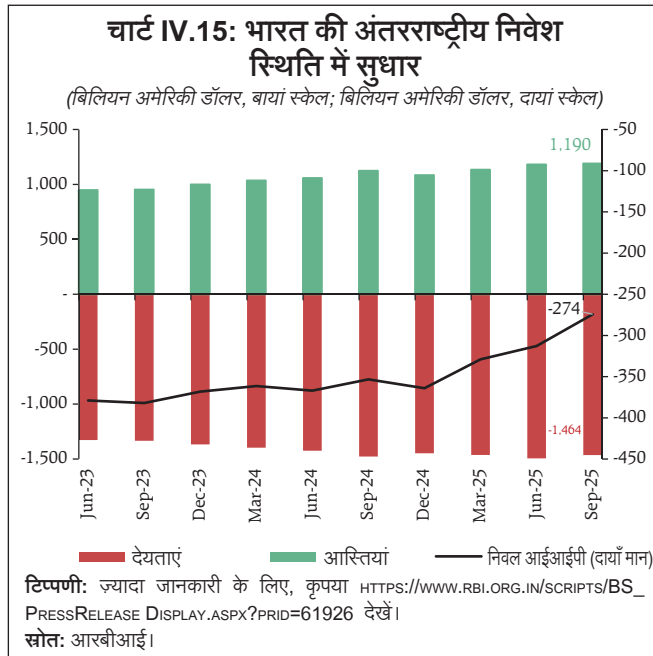
संकेतकों में स्पष्ट है। ऋण सेवा अनुपात और निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी)-से-जीडीपी अनुपात में सुधार हुआ, और बाहरी ऋण-और-जीडीपी अनुपात 20 प्रतिशत से नीचे रहा (चार्ट IV.13)। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत से सितंबर 2025 के अंत में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 746.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि जून 2025 के

अंत में यह 746.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम हो गया।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार संतोषजनक बना हुआ है, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात के लिए कवर प्रदान करता है और बकाया विदेशी ऋण के लगभग 92 प्रतिशत के लिए एक कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.14)⁴¹



⁴¹ 09 जनवरी 2026 तक, वस्तुओं और सेवाओं के लिए आयात कवर लगभग नौ माह था।



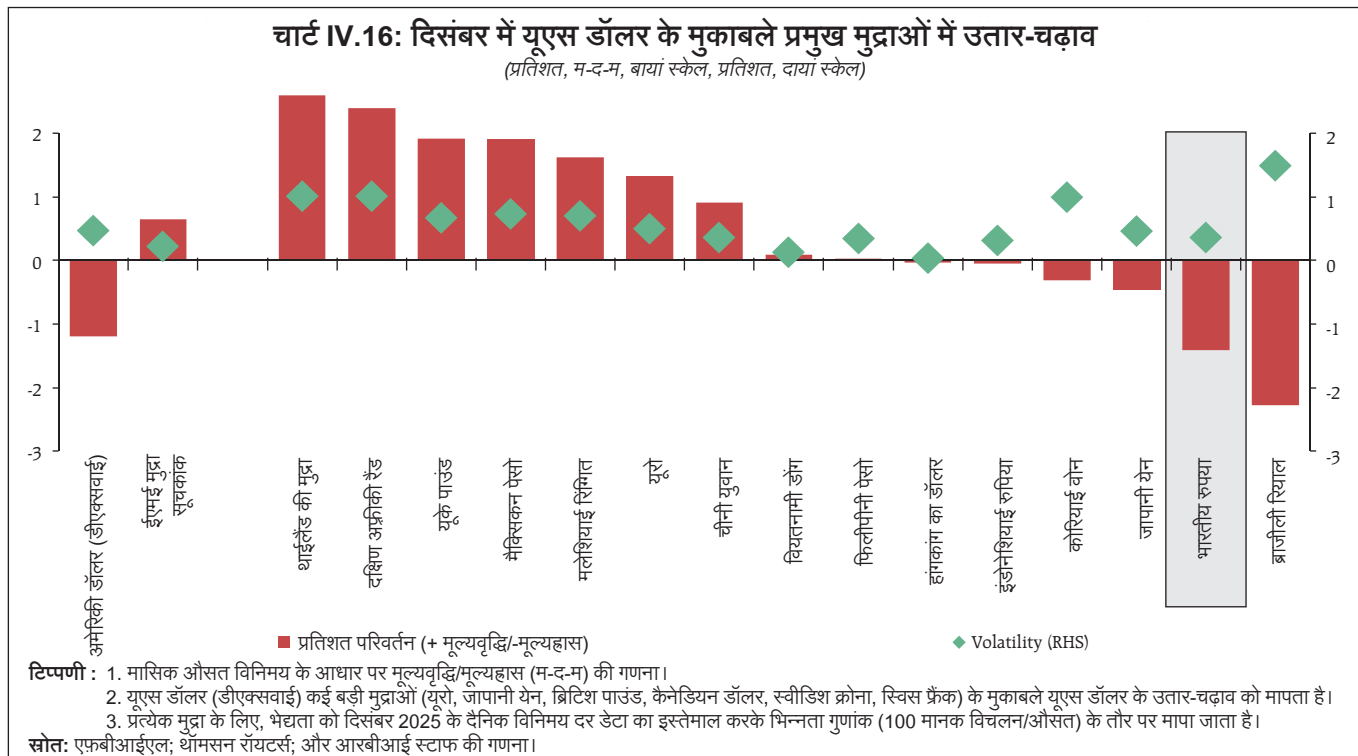
वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत के निवल आईआईपी में सुधार हुआ (चार्ट IV.15)।⁴² यह सुधार भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों में कमी और भारतीय

निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव से प्रेरित था।⁴³

विदेशी मुद्रा बाजार

विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के आसपास की अनिश्चितता के दबाव में दिसंबर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (आईएनआर) का अवमूल्यन हुआ (चार्ट IV.16)। आईएनआर की अस्थिरता, जैसा कि भिन्नता के गुणांक द्वारा मापा जाता है, अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही। जनवरी में अब तक (19वें स्थान तक) रुपये में दिसंबर के अंत के स्तर से 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई है।

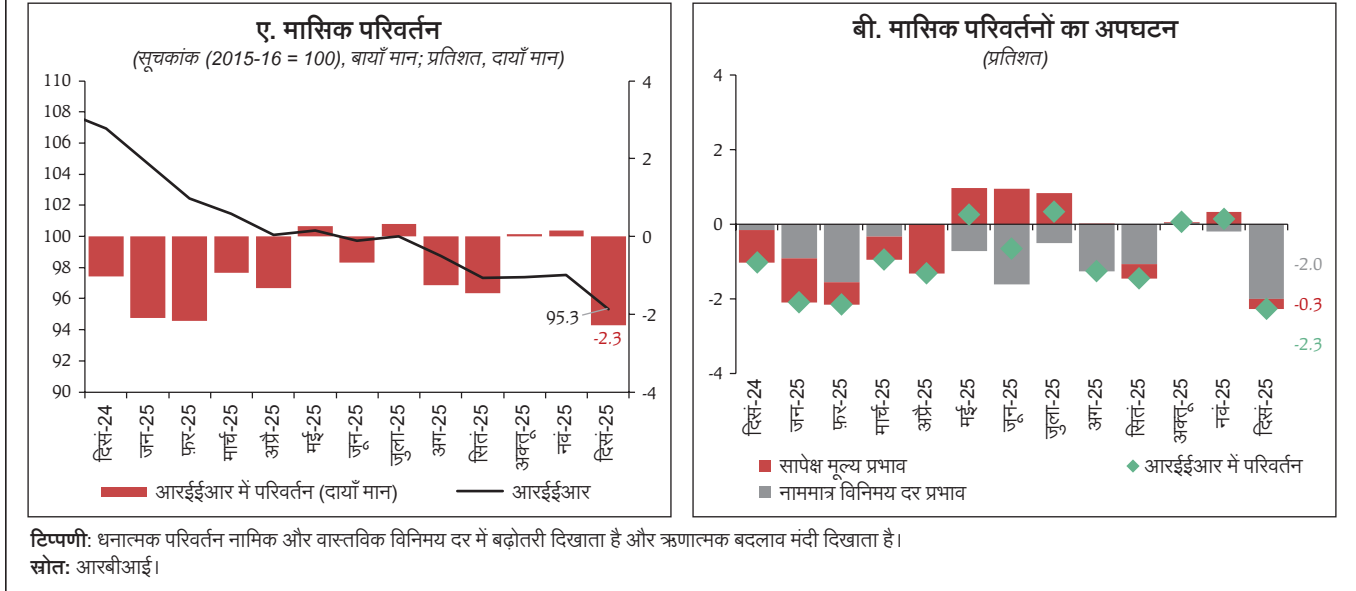
वास्तविक प्रभावी शब्दों में, भारतीय रुपये में नाममात्र प्रभावी शर्तों में मूल्यहास और भारत में अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति के कारण दिसंबर में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ (चार्ट IV.17)।



⁴² इसमें 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार हुआ और यह (-)274.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

⁴³ भारत की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं का अनुपात सितंबर में सुधरकर 81.3 प्रतिशत हो गया, जो जून में 79.1 प्रतिशत था।

चार्ट IV.17: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव



V. निष्कर्ष

वर्ष 2026 की शुरुआत भू-राजनीतिक दबाव में वृद्धि के साथ हुई, जो वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप, मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष, रूस-यूक्रेन शांति समझौते के आसपास की अस्पष्टता और ग्रीनलैंड पर विवाद के बढ़ने जैसे घटनाक्रमों से चिह्नित है, जो सभी अभी भी बढ़े हुए भू-आर्थिक जोखिमों और आगे की नीतिगत अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं।

इन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी, अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति आगे चलकर आशावाद के लिए आधार प्रदान करती है। वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान से संकेत मिलता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत ने बाह्य क्षेत्र के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से अपने निर्यात में विविधता लाने और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। देश वर्तमान में यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 50 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 देशों या समूहों के साथ व्यापार वार्ता में लगा हुआ है⁴⁴ दिसंबर के महीने में भारत ने न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार वार्ता समाप्त की। वर्ष 2025 में प्रमुख आर्थिक सुधार भी देखे गए, जिनमें कर संरचनाओं का युक्तिकरण, श्रम बाजार सुधारों के लिए श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन और

वित्तीय क्षेत्र के विनियमन शामिल हैं, जिनमें से सभी से विकास की संभावनाओं को मजबूत करने की उम्मीद है।⁴⁵

भारत में रिजर्व बैंक की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25 पर ने बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता को रेखांकित किया, जो मजबूत पूंजी बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत लाभप्रदता द्वारा समर्थित है। दिसंबर 2025 में जारी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट परिणामों ने प्रतिकूल परिदृश्यों में नुकसान का सामना करने और विनियामक न्यूनतम से ऊपर पूंजी बफर बनाए रखने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आघात-सहनीयता की पुष्टि की। आगे बढ़ते हुए, नीति नवाचार और स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण, और विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता में सुधार और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद मिलनी चाहिए।

⁴⁴ भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करने के अन्य उपायों में निर्यात ऋण की लागत को कम करना, वित्त तक पहुंच का विस्तार करना और भारत के निर्यात ब्रांड को मजबूत करना शामिल है।

⁴⁵ आरबीआई द्वारा किए गए प्रमुख विनियामक उपायों में 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्रों/दिशानिर्देशों को 244 कार्य-वार मास्टर निदेशों में समेकित करना, फेमा नियमों का सरलीकरण, ईसीबी नियमों को युक्तिसंगत बनाना और बैंकों को कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए धन देने में सक्षम बनाना शामिल है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। पूंजी बाजार में, केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए विनियामक अनुपालन को आसान बनाया गया था, जिससे बेहतर पहुंच संभव हो सकी।

अनुबंध

सारणी A1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

घटक	2025-26 में शेयर का (प्रतिशत)	भारत अंशदान (प्रतिशत अंक में)		2023-24 (एफआरई)	2024-25 (पीई)	2025-26 (एफएई)
		2024-25 (पीई)	2025-26 (एफएई)			
I. कुल उपभोग व्यय	65.2	4.3	4.5	5.9	6.5	6.8
निजी	56.3	4.0	4.0	5.6	7.2	7.0
सरकार	8.9	0.2	0.5	8.1	2.3	5.2
II. सकल पूंजी निर्माण	36.7	2.5	2.6	10.5	6.7	7.0
निश्चित निवेश	33.8	2.4	2.6	8.8	7.1	7.8
III. निवल निर्यात	-2.5	2.3	-1.9	-384.8	71.5	-217.8
निर्यात	21.4	1.4	1.4	2.2	6.3	6.4
आयात	24.0	-0.9	3.2	13.8	-3.7	14.4
IV. सकल घरेलू उत्पाद	100.0	6.5	7.4	9.2	6.5	7.4

टिप्पणियाँ: अन्य शेष वस्तुओं के कारण घटक कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

एफआरई: पहला संशोधित अनुमान; पीई: अनंतिम अनुमान; एफएई: पहला अग्रिम अनुमान।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

सारणी ए2: वास्तविक जीवीए वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	2025-26 (प्रतिशत) में शेयर	भारत अंशदान (प्रतिशत में)		2023-24 (एफआरई)	2024-25 (पीई)	2025-26 (एफएई)
		2024-25 (पीई)	2025-26 (एफएई)			
I. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	13.8	0.7	0.4	2.7	4.6	3.1
II. उद्योग	21.2	1.0	1.2	11.0	4.5	5.8
खनन और उत्खनन	1.8	0.1	0.0	3.2	2.7	-0.7
विनिर्माण	17.1	0.8	1.2	12.3	4.5	7.0
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	2.2	0.1	0.0	8.6	5.9	2.1
III. सेवाएं	65.0	4.8	5.7	9.2	7.5	8.8
निर्माण	9.1	0.8	0.6	10.4	9.4	7.0
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	18.5	1.1	1.4	7.5	6.1	7.5
वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं	24.4	1.7	2.4	10.3	7.2	9.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	13.0	1.1	1.3	8.8	8.9	9.9
IV. बुनियादी कीमतों पर जीवीए	100.0	6.4	7.3	8.6	6.4	7.3

टिप्पणी: एफआरई: पहला संशोधित अनुमान; पीई: अनंतिम अनुमान; एफएई: पहला अग्रिम अनुमान।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ की गणना।